अमर उजाला

नई दिल्ली ■ मंगलवार, 30 सितंबर 2025

प्रवाह

77 साल बेमिसाल

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

अपने डर को खुद तक ही सीमित रखें, लेकिन अपने साहस को दूसरों के साथ साझा करें। -रॉबर्ट लुई स्टीवेन्सन

अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप जिस पाकिस्तान को कोसते थे, आज उसके प्रधानमंत्री और सैन्य प्रमुख का स्वागत-सत्कार कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप कभी अमेरिका, तो कभी चीन की गोद में बैठता दिख रहा है। ये स्वार्थ के खेल हैं, जो भारत से अतिरिक्त कूटनीतिक सतर्कता की मांग करते हैं।

स्वार्थ के खेल

एक ओर अमेरिका के वाणिज्य सचिव भारत और ब्राजील जैसे देशों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर का हाल ही में अमेरिका में जिस तरह से स्वागत-सत्कार किया गया, उससे एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ है कि अमेरिका, पाकिस्तान और आतंकवाद के बीच गठजोड़ के पुख्ता प्रमाणों को दरकिनार करने का मन बना चुका है। पाकिस्तान को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है, उसकी तो नीति ही रही है, जिससे फायदा मिले, उस ओर झुक जाने की। व्हाइट हाउस से जारी तस्वीरों में इस मुलाकात का दिलचस्प दृश्य दिखता है। अव्वल तो राजनीतिक नेतृत्व की बैठक में सैन्य प्रमुख की उपस्थिति ही काफी कुछ कहती है, पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख का ट्रंप को दुर्लभ खनिजों का नमूना दिखाना दर्शाता है कि पड़ोसी मुल्क में व्यापार भी सेना ही करती है। दरअसल, कुछ देश ऐसे होते हैं, जिन पर अपने सामरिक हितों को साधने के लिए बड़ी शक्तियों की नजर रहती है। पाकिस्तान की हालत भी कुछ ऐसी ही है। अतीत में हमने अफगानिस्तान का उदाहरण देखा, जिस पर पहले रूस, फिर अमेरिका और अब चीन की नजर है। कुछ समय पहले ट्रंप ने अफगानिस्तान को चेतावनी दी थी कि वह बगराम एयरबेस अमेरिका के हवाले कर दे, जिसे अफगानिस्तान ने ठुकरा दिया था। ऐसे में मुमकिन है कि अफगानिस्तान पर शिकंजा कसने के लिए ही अमेरिका पाकिस्तान को साध रहा हो। पाकिस्तान पहले ही अराजकता, गरीबी, कर्ज, अस्थिरता और धार्मिक कट्टरता से घिरा है। नहीं भूलना चाहिए कि यह वही पाकिस्तान है, जहां घुसकर अमेरिका ने आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारा था और आज वही पाकिस्तान अपनी संप्रभुता पर हुए उस हमले को भूलकर अमेरिका से नजदीकी बढ़ाने की हरसंभव कोशिश कर रहा है। दरअसल, पाकिस्तान की प्रकृति और वृत्ति कुछ ऐसी ही है। इसका नीति से कोई लेना-देना नहीं, और न ही हम सामान्य आदर्शों की कसौटी पर इसका

मूल्यांकन कर सकते हैं। यह विशुद्ध अवसरवाद है, जिसमें पाकिस्तान दोनों महाशक्तियों की गोद में बैठकर फायदे लेना चाहता है। चीन इन स्थितियों पर सतर्कता के साथ नजर रखे हुए है, जिसने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है। वैश्विक युद्धों और ट्रंप-टैरिफ के दौर में जब सभी देश सिर्फ अपने-अपने हित देख रहे हैं, तो यह आशंका वाजिब है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद नए रूप में उभरने लगे। ऐसे में, भारत के लिए जरूरी है कि वह पूरी कूटनीतिक सतर्कता बनाए रखते हुए आगे बढ़े और साथ ही पाकिस्तान के दोहरे रवैये की पोल भी खोलता रहे, जैसा उसने संयुक्त राष्ट्र में किया।

यूनुस को आखिर क्या डर सता रहा है

संयुक्त राष्ट्र हो या चीन, मोहम्मद यूनुस हर जगह भारत विरोधी राग अलाप रहे हैं। म्यांमार में मानवीय गलियारे के निर्माण पर उन्होंने अमेरिका का समर्थन किया है, जबकि सेना इसका विरोध कर रही है। अब बीएनपी ने अवामी लीग का समर्थन कर उनकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं कि कहीं हसीना की वापसी न हो जाए।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस, शेख मुजीब उर रहमान के अनुयायी और एक सामाजिक उद्यमी होने से काफी आगे निकल चुके हैं, जिन्हें कभी तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गर्व के साथ 'ग्रामीण' टेलीफोन कॉल करके देश के दूरसंचार की दुनिया में प्रवेश की घोषणा की थी। आज वही यूनुस, हसीना पर बंदूक ताने हुए हैं, जिन्हें बीते वर्ष सत्ता से बेदखल कर दिया है। वह भारत पर बांग्लादेश की प्रगति में अड़ंगा डालने का आरोप भी लगा रहे हैं।

यूनुस ने हसीना और भारत के खिलाफ अपना अभियान तेज करते हुए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कई नेताओं से मिलकर शिकायत की कि भारत छोटे पड़ोसियों की समुद्री पहुंच बाधित कर रहा है, साथ ही भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को लेकर भी रोना रोया। इससे पहले उन्होंने अपनी चीन यात्रा के वक्त भी ऐसा ही कुछ किया था। वह दक्षिण-पूर्व एशियाई समूह आसियान की सदस्यता हासिल कर भारत के प्रभाव से बाहर निकलने की जल्दी में हैं। उन्होंने ट्रंप प्रशासन को यह भी बताया कि उन्होंने सार्क को पुनर्जीवित करने के लिए 'तेज प्रयास' शुरू कर दिए हैं। संयोग से सार्क की शुरुआत 1970 के दशक में जियाउर रहमान ने की थी, जो 'शत्रुतापूर्ण' भारत से अलग होने के इच्छुक थे। यूनुस ने कहा, 'सार्क का पूरा विचार बांग्लादेश में पैदा हुआ था। हमने सार्क को बढ़ावा देकर उस विचार को दक्षिण एशियाई क्षेत्र में एक से दूसरी राजधानी तक फैलाया। हमारा इतिहास हमें यह मौका देता है, लेकिन किसी तरह से एक देश की राजनीति में यह फिट नहीं बैठता, जिसका हमें भारी खेद है।'

महेंद्र वेद
वरिष्ठ पत्रकार

सीमा पार पाकिस्तान से उरी में हुए आतंकी हमले के बाद 2016 में भारत ने सार्क में अपनी भागीदारी रद्द कर दी थी। उस वक्त भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी शिखर सम्मेलन से हट गए थे। लेकिन, आज भारत न तो अफगानिस्तान और न ही बांग्लादेश पर भरोसा जता सकता है, जो 1971 में पाकिस्तान की सेना द्वारा किए गए हत्याचार को भुलाकर उसी के साथ दोस्ती की पींगें बढ़ा रहा है।

बांग्लादेश में पाकिस्तान उतनी ही बड़ी हकीकत है, जितना कि वहां पर चीन का बढ़ता प्रभाव। निस्संदेह, अमेरिका इन सबमें सबसे बड़ा है, जिसके सैकड़ों सैनिक बांग्लादेश-म्यांमार सीमा पर एक 'मानवीय गलियारे' पर काम करने के लिए तैनात हैं। यूनुस ने अपनी न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान यूरोपीय देशों से भी इसके लिए समर्थन मांगा। हालांकि, जनरल जमान इसके विरोध में हैं। चीन का मुकाबला करने के लिए बनाए गए इस गलियारे का भविष्य अनिश्चित है। यह सर्वविदित है कि बांग्लादेश की गतिशीलता अक्सर उसके छात्रों और युवाओं की भूमिका से निर्धारित होती है। हाल ही में हुए तीन विश्वविद्यालयों के चुनावी नतीजे देश के लिए गंभीर संकेत दे रहे हैं। अधिकारियों को इन चुनावों को संपन्न कराने और नतीजे घोषित करने में चार दिन लग गए। यदि विश्वविद्यालय के चुनाव ही चुनौती पेश करते हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूनुस ने अगले साल राष्ट्रीय चुनाव कराने का जो वादा किया है, उन्हें कैसे करा पाएंगे। बांग्लादेश की सेना कानून-व्यवस्था की निगरानी के लिए खड़ी है, क्योंकि नौकरशाही और पुलिस का एक बड़ा हिस्सा, जिसे नए शासकों ने 'फासीवादी' हसीना शासन का समर्थक करार दिया है, नाराज है और चुपचाप असहयोग कर रहा है।

विश्वविद्यालयों के चुनावों में इस्लामी कट्टरपंथियों की जीत भारत की चिंता बढ़ाती है, जिनमें सबसे बड़ी हार पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की हुई है। हसीना की बेदखली और अवामी लीग पर प्रतिबंध के बाद बीएनपी को स्पष्ट विजेता माना जा रहा था, लेकिन जमीनी हालात बदल गए, क्योंकि सत्ता में वापसी के प्रति आश्वस्त बीएनपी कार्यकर्ता सड़कों पर उपद्रवी होने की वजह से अलोकप्रिय हो गए हैं। जमात का बढ़ना काफी कुछ कहता है, लेकिन इसकी टक्कर यूनुस के आशीर्वाद से बनी 'किंग्स पार्टी' नेशनल सिटीजंस पार्टी (एनसीपी) से भी है। हालांकि, एनसीपी अब तक न तो अपने कैडर बना पाई है और न ही अन्य बेहतर संगठित समूहों के खिलाफ जमीनी स्तर पर अपनी पकड़। एनसीपी ने यूनुस पर देश का संविधान बदलकर 'जुलाई चार्टर' को लागू करने का दबाव बनाया, हालांकि वह सेना प्रमुख जमान की वजह से इसमें सफल नहीं हो सके।

यूनुस हसीना की वापसी को लेकर भी डरे हुए हैं। अवामी लीग बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी जड़ें काफी गहरी हैं और उसके पास बड़ा कैडर है, भले ही उसके कई नेता या तो जेल में हैं, या भाग रहे हैं या फिर निर्वासित हैं। विडंबना यह है कि अवामी लीग को बीएनपी का समर्थन मिला है। जब हसीना को सत्ता से बेदखल किया गया, तो उनकी प्रतिद्वंद्वी जिया की प्रतिक्रिया शत्रुतापूर्ण नहीं थी। संभवतः जिया ने इस्लामवादियों के एकजुट होने का पूर्वानुमान लगा लिया था। अब, बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल आलमगीर ने मांग की है कि हसीना और अवामी लीग पर कथित अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाए और दोषी पाए जाने पर सजा दी जाए। लेकिन, उन्हें चुनाव से बाहर रखने का मतलब होगा, उन्हीं गलतियों को दोहराना, जो हसीना ने की थीं। नाराज इस्लामवादियों ने उन्हें हसीना का 'एजेंट' कहा है।

दरअसल, जमात और एनसीपी, दोनों ही अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए समय चाहती हैं, जबकि बीएनपी तय समय पर चुनाव। फिलहाल, बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, लेकिन बहुमत में आने की उम्मीद कम ही है। फिर उसे इस्लामवादियों के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। शायद, मौजूदा वैश्विक रुझान को देखते हुए यूनुस और पश्चिमी आकाओं को एक दक्षिणपंथी और अति-दक्षिणपंथी गठबंधन ही चाहिए। लेकिन इस्लामवादियों के साथ ऐसा नहीं है, जो मुक्ति संग्राम के विरोधी थे। वे बीएनपी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, जो दक्षिणपंथी होने के बावजूद भारत की आलोचना करती है, लेकिन 'मुक्ति' के सिद्धांतों को बढ़ावा देती है। इस्लामवादी संविधान में बदलाव करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के लिए अभियान चला रहे हैं, जिससे उन्हें संसदीय वैधता हासिल करने और सत्ता का केंद्र बनने का मौका मिलेगा। ऐसे हालात में, बांग्लादेश में चुनाव चाहे फरवरी में हों या बाद में, उसकी पहचान की खोज फाइनल नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा सेमीफाइनल ही हो सकते हैं।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

चार्ल्स वैगनर

एक सच्चा इन्सान अपने विचारों को अपने स्वभाव और रुचियों के अनुसार इस्तेमाल करता है, न कि उत्सुकता व जल्दबाजी के साथ, जो कभी गहरी भावना या सही मुकाम तक नहीं पहुंचती।

विचारों का मैदान करतब दिखाने की जगह नहीं है

हमारे विचारों की दुनिया में अराजकता फैली हुई है। यह ऐसा है, जैसे हम जंगल में बिना किसी दिशासूचक यंत्र या सूरज के भटक रहे हों, और अनगिनत छोटी-छोटी बातों में उलझकर रास्ता भूल गए हों। जब इन्सान को यह समझ आता है कि उसका एक लक्ष्य है, और वह लक्ष्य है एक बेहतर इन्सान बनना, तो वह अपने विचारों को उसी तरह व्यवस्थित करता है। वह हर उस सोच या निर्णय को ठुकरा देता है, जो उसे बेहतर और मजबूत नहीं बनाता। और सबसे पहले वह अपने विचारों से खुद को बहलाने की आम विरोधाभासी प्रवृत्ति से दूर भागता है।

विचार एक उपकरण है, जिसका अपना खास काम है। यह कोई खिलौना नहीं है। उदाहरण के लिए, एक चित्रकार का स्टूडियो देखें। वहां हर चीज एक खास मकसद के लिए रखी होती है। लेकिन अगर उस स्टूडियो में बंदरों को छोड़ दिया जाए, तो वे बेंच पर चढ़ेंगे, रस्सियों से झूलेंगे, ब्रश से खेलेंगे, रंग चबाएंगे और कैनवास को फाड़कर देखेंगे कि उसके पीछे क्या है। हो सकता है उन्हें यह सब मजेदार लगे, लेकिन स्टूडियो बंदरों के खेलने के लिए नहीं बनाया गया। उसी तरह, विचारों का मैदान भी करतब दिखाने की जगह नहीं है। एक सच्चा इन्सान अपने विचारों को अपने स्वभाव और रुचियों के अनुसार इस्तेमाल करता है, न कि उत्सुकता व जल्दबाजी के साथ, जो कभी गहरी भावना या सही मुकाम तक नहीं पहुंचती।

एक और आदत, जिसमें सुधार की जरूरत है, वह है हर समय खुद को जांचने और विश्लेषण करने की बीमारी। मैं यह नहीं कह रहा कि आत्मनिरीक्षण या अपनी गलतियों को समझना गलत है। अपनी सोच और व्यवहार को समझने की कोशिश अच्छे जीवन का हिस्सा है। लेकिन हर पल अपनी जिंदगी और विचारों को टुकड़ों में बांटकर देखना, जैसे कोई मशीन हो, यह गलत है। यह समय की बर्बादी है और लक्ष्य से भटकाने वाला है। अगर कोई चलने से पहले अपने शरीर की पूरी जांच-पड़ताल शुरू कर दे, तो वह शायद एक कदम भी न चल पाए। आपके पास जो है, उसी के साथ आगे बढ़ें। बस इतना ध्यान रखें कि आप गिरें नहीं और अपनी ताकत का समझदारी से इस्तेमाल करें। ज्यादा सोचने और शक करने वाले लोग जल्दी ही निष्क्रिय हो जाते हैं। थोड़ा सा सामान्य ज्ञान यह समझने के लिए काफी है कि इन्सान का जीवन खुद में डूबे रहने के लिए नहीं बना। क्या आपको यह नहीं लगता कि सामान्य ज्ञान नाम से जो कुछ भी कहा जाता है, वह अन्य दिनों के सामान्य ज्ञान के रीति-रिवाजों की तरह दुर्लभ होता जा रहा है? यह पुरानी कहानी बन गई है। हमें कुछ नया चाहिए होता है और हम एक बनावटी अस्तित्व, जीवन का एक परिष्कार रचते हैं, जिसे पाने के लिए अशिष्ट भीड़ के पास साधन नहीं होते। अलग पहचान बनाना कितना सुखद है! खुद को तर्कसंगत प्राणियों की तरह व्यवहार करने और अपने पास उपलब्ध साधनों का उपयोग करने के बजाय, हम पूर्ण प्रतिभा के बल पर, सबसे आश्चर्यजनक एकल पर पहुंच जाते हैं।

सुधार पर ध्यान दें

सूत्र

मन में कई विचार आते हैं और हम उनमें उलझकर रह जाते हैं। विचारों की उलझन में हम जीवन के अर्थ खो देते हैं। इसलिए जरूरी है कि एक लक्ष्य निर्धारित करें और जो हमारे पास है, उसी का उपयोग करके जीवन को सुंदर बनाएं। हरेक इन्सान में कोई न कोई खामी होती ही है, ध्यान सिर्फ गलतियों पर नहीं, बल्कि सुधार पर भी दें और आगे बढ़ते रहें।

दूसरा पहलू

वैज्ञानिक मलिक ने 50 साल पहले बता दिया था कि ललितपुर में यूरेनियम के भंडार हैं, जिस पर शोध चल रहा है।

यहां हो सकते हैं यूरेनियम के भंडार

पचास साल पहले *अमर उजाला* को दिए साक्षात्कार में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पहले और वैज्ञानिक कुलपति डब्ल्यू यू मलिक ने झांसी मंडल के ललितपुर में यूरेनियम के भारी भंडार होने की जानकारी दी थी। तब वैज्ञानिकों की टीम ने राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संस्थाओं से आर्थिक मदद के लिए इस संबंध में अपनी रिपोर्ट साझा की थी। उसके बाद नब्बे के दशक में परमाणु ऊर्जा विभाग की रिसर्च टीम ने ललितपुर के मड़ावरा क्षेत्र को यूरेनियम संभावित क्षेत्र के रूप में पहचाना था। रिसर्च टीम ने वर्ष 1998 में अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट में यूपी के ही सोनभद्र जिले में यूरेनियम के भंडार की संभावना जताई थी।

अमरनाथ

नब्बे के दशक में रिसर्च टीम ने ललितपुर के मड़ावरा क्षेत्र को यूरेनियम संभावित क्षेत्र के रूप में पहचाना था।

परमाणु ऊर्जा विभाग की टीम ने दो महीने पहले ही सोनभद्र के दुद्धी तहसील क्षेत्र में खोदाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि करीब 1,100 फुट की गहराई तक खोदाई की जा रही है। संकेत हैं कि सोनभद्र के कुदरी पहाड़ और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 700 टन यूरेनियम का भंडार हो सकता है। भूगर्भीय अध्ययन बताते हैं कि ये दोनों क्षेत्र विंध्य शैल समूह से जुड़े हुए हैं। इसका फैलाव बुंदेलखंड तक है। इस क्षेत्र की चट्टानों में लोहा, सोना, चूना पत्थर और अन्य खनिज के अलावा यूरेनियम के भी मिलने की संभावना है। वैसे ललितपुर की गिनती यूपी के पिछड़े जिले में होती है, पर यह जनपद प्राकृतिक सौंदर्य और खनिज संसाधनों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा की संघटक इकाई परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय की टीम ने 1990 से लेकर 1995 तक ललितपुर के टोड़ी पिसनारी समेत आसपास के आधा दर्जन गांवों में जांच की और यूरेनियम की उपलब्धता के साक्ष्य जुटाए। जांच में क्या कुछ निकला, इसका खुलासा होना अभी बाकी है।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, झांसी के क्षेत्रीय अधिकारी आशीष बताते हैं कि पिसनारी, गौना, लखंजर, पापड़ा, सकरा, धनगना, उल्दना खुर्द, सौलदा, कुर्रट आदि गांवों के आसपास यूरेनियम होने की संभावना है।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, झांसी के क्षेत्रीय अधिकारी आशीष चौधरी बताते हैं कि मड़ावरा ब्लॉक के पिसनारी, गौना, लखंजर, पापड़ा, सकरा, धनगना, उल्दना खुर्द, सौलदा, कुर्रट आदि गांवों के आसपास यूरेनियम होने की संभावना है। हालांकि, अब तक इस क्षेत्र में कोई चिह्नांकन नहीं किया गया है। झारखंड ही नहीं, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में भी यूरेनियम के बड़े भंडार मिल चुके हैं, लेकिन सोनभद्र और ललितपुर यूरेनियम के छोटे भंडार भी अहम माने जा रहे हैं। यदि यहां यूरेनियम या अन्य खनिज तत्व मिलते हैं, तो यह क्षेत्र के साथ ही प्रदेश और देश के लिए अहम होगा, लेकिन कुछ स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चिंताओं पर भी ध्यान देना होगा।

आंकड़े

एआई का खौफ

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कई देशों के लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं कि यह उनकी नौकरियां छीन लेगा।

भारत	36%
पाकिस्तान	31%
दक्षिण अफ्रीका	23%
मेक्सिको	21%
केन्या व चिली	20-20%

आंकड़े उनके जो मानते हैं कि एआई उनकी नौकरियां छीन लेगा, प्रतिशत में | स्रोत : GPO-AI, SRITS

औरंगजेब जब ब्रह्मपुरी पहुंचा, लोगों को भय था कि वह विट्ठल भगवान को क्षति न पहुंचाए। भक्त प्रह्लाद बुवा ने लोगों से कहा, 'आप लोग भयभीत न हों।'

मेरे विट्ठल को कोई छू भी न पाएगा

अंतर्यात्रा
संकलित

पंढरपुर में प्रह्लाद बुवा नाम के बड़े संत हुए हैं। उन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज के *अमृतानुभव* ग्रंथ का संस्कृत अनुवाद किया था। बताते हैं कि वह बचपन से ही श्रीविट्ठल भगवान के ध्यान में मग्न रहा करते थे। बताया तो यहां तक जाता है कि रात्रि की आरती होने के बाद भगवान विट्ठल दौड़कर अपने भक्त प्रह्लाद के घर पहुंच जाते थे और रात भर दोनों के बीच प्रेम भरे संवाद होते थे। पंढरपुर में इतनी मान्यता थी कि प्रह्लाद बुवा के घर जाकर भगवान को आवाज देकर जगाया जाता था।

शिवाजी महाराज के बाद औरंगजेब ने महाराष्ट्र पर चढ़ाई की थी। उस वक्त पंढरपुर के निकट ब्रह्मपुरी में वह पांच वर्ष तक अपना डेरा डाले रहा। औरंगजेब मंदिरों और मूर्तियों को खंडित करने के लिए कुख्यात था, इसलिए पंढरपुर में कई भक्तों ने आशंका जताई कि कहीं उसकी सेना आकर विट्ठल मंदिर में भी उत्पात न मचाए। इस पर भक्त प्रह्लाद बुवा ने लोगों से कहा, 'आप लोग भयभीत न हों, मेरे विट्ठल को कोई छू भी न पाएगा।' जब तक औरंगजेब ब्रह्मपुरी में रहा, तब तक प्रह्लाद बुवा ने विट्ठल भगवान की प्रतिमा की रक्षा ऐसे की, जैसे माता यशोदा कहती थीं कि मेरे लाल को किसी की नजर न लगे। वह मूर्ति को अपने हृदय से लगाकर साथ रखते थे। मराठाओं का फिर से साम्राज्य होने के बाद प्रह्लाद महाराज ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर विट्ठल भगवान को फिर स्थापित करवाया।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 30 सितंबर, 1953

अमेरिका की चीन को धमकी, हिंदचीन में हस्तक्षेप सहन नहीं

हिंदचीन में हस्तक्षेप सहन न होगा

अमेरिकी विदेश मंत्री डलेस ने भूतपूर्व अमेरिकी सैनिकों के बीच कहा कि यदि चीन ने हिंदचीन में कोई संगीन कार्रवाई की, तो हम सख्त कदम उठाएंगे, जो कि उसके लिए घातक साबित होंगे।

चिकित्सकों की कमी से बड़ी कोई बीमारी नहीं

उत्तर प्रदेश में स्वीकृत चिकित्सकों की संख्या का 55 फीसदी ही उपलब्ध है। क्या वजह है कि ग्रामीण इलाके लगातार चिकित्सकों के अकाल से जूझ रहे हैं?

विजय त्रिपाठी

स्वास्थ्य

केंद्र सरकार ने देश भर में एमबीबीएस और एमएस-एमडी की 10 हजार सीटें बढ़ाने का फैसला किया है। इनमें कुछ सीटें डॉक्टरों की भीषण कमी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के हिस्से भी आएंगी। हालांकि, प्रदेश सरकार की ओर से एमबीबीएस की करीब 500 और एमडी-एमएस की करीब 200 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है। बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टरों की भीषण कमी से जूझ रहे प्रदेश की जरूरत क्या चंद डॉक्टरों से पूरी हो पाएगी। प्रदेश के अस्पतालों में स्वीकृत संख्या के करीब 55 फीसदी डॉक्टर ही उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो डॉक्टरों का बहुत ज्यादा अकाल है।

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कहीं 20, तो कहीं 50 फीसदी तक चिकित्सा शिक्षकों के पद खाली हैं। छोटे-छोटे शहरों को तो छोड़ ही दीजिए, राजधानी लखनऊ में डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में 37, केजीएमयू में 20, तो पीजीआई में 16 फीसदी पद खाली हैं। डॉक्टरों की कमी का सबसे बड़ा कारण

सरकारी अस्पतालों में काम का बहुत ज्यादा दबाव और उस हिसाब से कम वेतन है। क्वालिटी डॉक्टरों की एक बड़ी फौज बाबूगीरी में भी फंसी है। सरकारी क्षेत्र का खराब बुनियादी ढांचा, पदोन्नति की धीमी प्रक्रिया, और डॉक्टरों की उपलब्धता के लिए पर्याप्त प्रयास न होना भी इस समस्या को बढ़ाते हैं। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग में करीब 19,700 डॉक्टर तैनात हैं और करीब सात हजार से अधिक पद खाली हैं।

इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मुताबिक, एक हजार की आबादी पर एक डॉक्टर जरूरी है। उत्तर प्रदेश इस लक्ष्य से कोसों दूर है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने यह सुविधा दे दी है कि करीब 15 साल से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में पढ़ा सकेंगे। इसका विरोध हो रहा है। लेकिन चिकित्सा शिक्षकों की कमी को देखते हुए इस फैसले का स्वागत किया जा सकता है, क्योंकि सवाल यह भी उठता है कि बिना अध्यापक पढ़कर तैयार होने वाले ये विशेषज्ञ डॉक्टर भविष्य में प्रदेश की चिकित्सकीय तस्वीर बदल पाएंगे?

एमडी, एमएस और डीएम- एमसीएच की डिग्री लेने के बाद ये मेडिकल कॉलेज में अध्यापक का पेशा चुनते हैं, तो इसके पीछे सिर्फ आर्थिक कारण नहीं है, बल्कि उन्हें सम्मान और सुरक्षा चाहिए होती है। कई शिक्षकों ने बताया कि नियमित शिक्षक की निजी प्रैक्टिस करने पर रोक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में करीब 1.20 लाख रुपये प्रतिमाह मिलता है, जो नाकाफी है। दो से तीन साल में तबादला भी हो जाता है। समय से पदोन्नति नहीं होती है। इन तमाम खामियों पर विभाग को ध्यान देना होगा। यही नहीं, कॉलेजों में संसाधनों का अभाव, शोध के लिए माहौल की कमी, परिवार के लिए अनुकूल माहौल न होना आदि भी उनके कॉलेज छोड़ने की वजहें हैं। शिक्षण कार्य और उपचार के अलावा ढेर सारे कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेजों में बिजली, फायर सर्विस, सीवर निगरानी आदि सेवाओं के लिए कोई कैडर नहीं है। कोई अप्रिय घटना होने पर उनकी गर्दन फंसती है।

कई कालेजों में प्रधानाचार्य रहे व चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक की जिम्मेदारी निभा चुके डॉ. एनसी प्रजापति बताते हैं कि निश्चित तौर पर हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलना नई सोच का परिणाम है। कुछ वर्षों बाद इसका फायदा दिखेगा। लेकिन बेहतर यह होता कि जो कॉलेज पहले से चल रहे हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाता, फिर चरणबद्ध तरीके से नए कॉलेजों की ओर कदम बढ़ाया जाता। पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक बद्री विशाल कहते हैं कि सरकार को नई नीतियों के जरिये चिकित्सा शिक्षकों को आकर्षित करना चाहिए। छोटे जिलों में बच्चों के पढ़ने के लिए शैक्षिक गुणवत्ता वाले विद्यालय हों। जैसे संजय गांधी पीजीआई में केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्था है, उसी तरह से अन्य कॉलेजों के आसपास भी शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है। सीटें बढ़ाने की होड़ खत्म करके डॉक्टरों की कुशलता पर फोकस बढ़ाना होगा।

चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के मुताबिक, नए सिरे से चिकित्सा शिक्षा का पौधा रोपा जा रहा है। वर्ष 2027 के बाद प्रदेश में चिकित्सा शिक्षकों और अन्य डॉक्टरों की कमी दूर होने लगेगी। फिर भी जहां जैसी जरूरत है, वहां एनएचएम और संविदा के जरिये डॉक्टर तैनात किए जा रहे हैं। लेकिन, इसका एक पहलू यह भी है कि एक तरफ जहां डॉक्टरों को नौकरी में बनाए रखने के लिए सरकार लाखों जतन कर रही है, वहीं सीएचसी में तैनात डॉक्टरों को तीन महीने से मानदेय नहीं मिल सका है। ये महानिदेशालय से लेकर सीएमओ तक के चक्कर काट रहे हैं। इनका वेतन भी बड़े अस्पतालों में तैनात अपने बैचमेट से काफी कम ही है। गौरतलब है कि सीएचसी में ही सबसे ज्यादा जरूरतमंद मरीज आते हैं।

नवभारत टाइम्स • विचार

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 30 सितंबर 2025

जब अपने प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करते है और निष्पक्ष खेलते है, तभी क्रिकेट एक सुंदर खेल बनता है। – *ब्रायन लारा*

क्रिकेट का नुक़सान

एशिया कप खत्म हो चुका है, लेकिन उससे जुड़े विवाद जारी हैं। यह क्रिकेट टूर्नामेंट जितनी कड़वाहट के साथ शुरू हुआ था, उससे भी ज्यादा कड़वाहट छोड़कर जा रहा है। फाइनल के दिन और उसके बाद जो कुछ हुआ, उससे खेल की गरिमा को चोट पहुंची है।

माहौल का असर । भारत-पाकिस्तान रिश्तों के बीच क्रिकेट हमेशा से अहम फैक्टर रहा है। दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ, तो इसी के जरिये एक-दूसरे के प्रति गुस्सा भी निकाला गया। इस एशिया कप को लेकर शायद ही किसी के मन में संशय रहा हो। टूर्नामेंट की पहली गेंद फेंके जाने से पहले तनाव बढ़ना शुरू हो गया था। जब माहौल इस कदर कटुता से भरा हो, तो उसका असर दिखते देर नहीं लगती।

नकवी का विवादित रवैया

ACC की लापरवाही । दुर्भाग्य से एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पूरे मामले को बहुत ही लापरवाही और गैर पेशेवर ढंग से लिया - और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी इस लापरवाही का चरम थी। ACC की कमान इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के पास है। बतौर ACC प्रमुख, यह उनकी जिम्मेदारी थी कि आयोजन सफलतापूर्वक खत्म होता, लेकिन उन्होंने ही उसमें अड़ंगा लगा दिया। क्रिकेट इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पदाधिकारी ट्रॉफी लेकर चला गया हो और चैंपियन टीम खाली हाथ रहे।

खेल का मजाक । मैच रेफरी से जुड़ा विवाद हो या UAE मैच से पहले हुआ ड्रामा - पीसीबी के कदमों से क्रिकेट का केवल मजाक ही बना। कम से कम ट्रॉफी विवाद को आसानी से टाला जा सकता था। खिलाड़ियों के बीच मैदान पर बहस, स्लेजिंग, इशारेबाजी चलती है - पहली बार ऐसा हुआ कि ACC प्रमुख भी उसमें पार्टी बन गए। नकवी यह भूल गए कि इस इवेंट में उनकी भूमिका केवल PCB चीफ की नहीं है।

युद्ध उन्माद । नकवी ने आरोप लगाया था कि भारत खेल में राजनीति को ला रहा है, पर अब वह खुद ही क्रिकेट में युद्ध को घसीट लाए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट के जवाब में नकवी का मेसेज भ्रामक और क्रिकेट को और नुकसान पहुंचाने वाला है। खेल को इससे जो क्षति पहुंची है, उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है।

खेल भावना का ख्याल । नवंबर में ICC की बैठक होनी है। BCCI ने कहा है कि इसमें नकवी के आचरण को लेकर शिकायत दर्ज की जाएगी। क्रिकेट नई जमीन तलाश रहा है, खासकर एशिया में। एशिया कप का यही मकसद है, पर इस तरह के टूर्नामेंट से यह हासिल नहीं होगा। इसके लिए ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, जो खेल की भावना को समझते हों।

ऐवें कुछ भी

AI तेंदुए से बचाओ

किसी महाकवि ने कहा था, जीने के हैं चार दिन, बाकी हैं बेकार दिन...। हमारे ये चार दिन भी बेकार ही जा रहे हैं। फिलहाल जीवन भय में बीत रहा है। दो बड़ी मुसीबतें हैं जो जीने नहीं दे रही हैं। एक तो जंगली जानवर हैं जो मुंह उठाए लखनऊ की तरफ चले आ रहे हैं, दूसरे ये Gen Z, जो AI को अपना हथियार बनाए घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे भूत के हाथ भाला लग गया हो। जहां मन चाहे वहां प्रयोग हो रहा।

आलोक सिंह भदौरिया

बहरहाल, पिछले साल क्रिसमस पर एक बाघ महोदय लखनऊ आए थे। लगभग तीन महीने उन्होंने वन विभाग से खातिरदारी करवाई। बंधे हुए शिकार का स्वाद उठाया, कुल मिलाकर 24 मवेशियों को इस नश्वर संसार से मुक्त करा दिया। कुछ होम सिकनेस टाइप फीलिंग हुई होगी, सो एक दिन उन्होंने सरकार को पुनः सेवा का अवसर दिया और वन विभाग ने उन्हें पिंजरे में बैठाकर जंगल में छोड़ दिया। जाने से पहले उनका कंप्लीट बॉडी चेकअप भी हुआ। फिर जंगल-जंगल बात चली, इस आवभगत का समाचार पाकर एक युवा तेंदुआ भी लखनऊ आ चुका है। इधर-उधर न भटकर तेंदुआ सीधे कैंट पहुंच गया। इसके बाद AI ने करतब दिखाना शुरू किया। शहर के हर गली-कूचे से तेंदुए के फोटो आने लगे। कहीं गाड़ी के पीछे, कहीं गेट के बाहर। कहीं लपकता, कहीं दार्शनिक मुद्रा में। नेता नगरी ने हल्ला बोलना शुरू कर दिया कि मवेशी तो छोड़िए तेंदुए तक राजधानी में छुट्टा घूम रहे हैं। खैर, पुलिस प्रशासन हरकत में आया तो पता चला कि एक Gen Z ने AI से तेंदुए को घर-घर में पहुंचा दिया।

सही समय पर कदम उठाया वरना जल्द ही शर्मा चाय, टुंडे कबाब, प्रकाश कुल्फी की दुकान पर तेंदुए की भीड़ के साथ फोटो आने वाली थी और लोग टैग करके लिखते युवा हृदय सम्राट तेंदुआ भइया के साथ फुर्सत के पलों में। सरकार से अनुरोध है कि तेंदुआ तो खैर कंट्रोल हो जाएगा इस AI का कुछ कीजिए। किसी दिन असली को ही AI समझकर उसे चपत जमा दी तो जीवन के चार दिनों का वहीं 'दी एंड' हो जाएगा।

एकदा

राहुल पाण्डेय

खीस की भेंट

दशकों तक हमारे घर गाय रही। नाम था झुमकलता। घर में तय था कि झुमकलता के बच्चा होगा, तो उसके खाने के लिए गुड़ और बांस की पत्तियां अली हुसैन मामा के यहां से ही आएंगी। फिर झुमकलता के दूध से बनी पहली खीस का एक बड़ा हिस्सा उनकी अम्मा के नाम रहेगा। खीस अवध से लेकर गढ़वाल तक का जाना-माना शब्द है। खीस यानी गाय-भैंस के बच्चा होने के बाद जो पहला दूध निकलता है, उसे उबालकर बनने वाला पकवान। खीस का कटोरा हाथ लगते ही अली हुसैन की अम्मा भी हाथ भर लंबी खीस निकालतीं। यहां जो खीस निकली, वो दांत चियारने वाली प्रसन्नता है। पर खीस प्रसन्नता में ही नहीं, लज्जा और बेबसी में भी निकलती है। खीस अंगिका में चिढ़, गुस्सा है तो खिसकना भी है। कन्नौजी में यह खीझ है। कुमाऊंनी में यह लाज-शर्म है तो गढ़वाली में लकीर और उकताहट भी। बघेली में यह दांत के मसूड़े, दुरूपयोग व उजाड़ होना है। वज्जिका में यह क्रोध है तो बुंदेली में हाथी के दिखाने के दांत। ब्रज में यह हानि, कमी, नष्ट और चौपट भी है। मगही में खीस चिढ़, कुढ़न है तो मैथिली में क्रोध भी है। जाहिर है कि खीस के इतने अर्थों को व्यक्त करने में इंग्लिश का grinning शब्द भी खिसिया जाता है।

AI Image

एशिया कप ने भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट डिप्लोमेसी को लेकर बना भ्रम तोड़ा

सुनो भाई ! यह कभी सिर्फ़ खेल नहीं रहा

इस कहानी का अंत अभिषेक शर्मा से हो सकता था, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 200 के स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा रन बनाए या फिर तिलक वर्मा, जिनकी पारी ने खिताबी जीत दिलाई - लेकिन क्रिकेट के देवता ने कुछ और ही तय कर रखा था। एशिया कप शुरू होने के पहले खिलाड़ियों से सवाल किया गया था कि वे क्या चाहते हैं? रिंकू सिंह ने जवाब दिया - 'विनिंग रन बनाना!' 6 मुकाबलों में बेंच पर बैठकर मैच घटते देखना, फिर फाइनल में मौका क्योंकि हार्दिक पंड्या चोटिल हो गए और उसमें भी आखिरी रन बनाने के लिए क्रीज पर पहुंच जाना - पोस्ट मैच एनालिसिस में रवि शास्त्री ने यह भी एनालाइज कर लिया कि रिंकू का एक करियर ज्योतिष में भी बन सकता है। हालांकि यह केवल किस्मत नहीं और न ही तुक्का - यह भरोसा है।

शैलेंद्र पांडेय

दूसरों से आगे । टूर्नामेंट की शुरुआत से ही टीम इंडिया को फेवरिट माना गया। क्रिकेट फैंस की ज्यादा दिलचस्पी यह जानने में थी कि फाइनल में भारत के खिलाफ कौन आता है। रैंकिंग के हिसाब से T-20 में नंबर वन टीम भारत के सबसे करीब पाकिस्तान है - सातवें नंबर पर। आठवें पर श्रीलंका, नौवें पर बांग्लादेश और 10वें पर है अफगानिस्तान। लेकिन, रैंकिंग के इस अंतर को साबित करना होता है असल खेल में, मैदान पर और टीम इंडिया ने वही किया।

गलतफहमी दूर हुई । ट्रॉफी उठाना (हालांकि सही में उठाने को नहीं मिली) बड़ा मोमेंट है और यह उपलब्धि इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि जिन परिस्थितियों में यह क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ।

भारत की जीत इसलिए बड़ी
- बायकॉट का शोर, जनता का प्रेशर था
- रिश्तो मे तनाव का असर मैदान पर दिखा
- अपने कद के अनुसार प्रदर्शन का दबाव

चंद महीनों पहले भारत और पाकिस्तान एक बड़े टकराव से गुजरे हैं, उस फ्रंट पर टेंशन कायम है, लोगों में गुस्सा भरा है - ऐसे में अगर BCCI या आयोजकों ने यह सोचा होगा कि खेल से माहौल सुधर जाएगा, तो उनकी गलतफहमी थी।

बाहर का तनाव । मैच से पहले कोच और कोचिंग स्टाफ से जुड़े एक्सपर्ट आमतौर पर यही सलाह देते हैं कि बाहर का शोर मत सुनो - बस खेल पर फोकस करो। लेकिन, आज के दौर में खुद को आइसोलेट कर लेना इतना आसान नहीं है। बाहर का तनाव सरकते हुए ड्रेसिंग रूम में पहुंच ही जाता है।

बस स्किल फैक्टर नहीं । इसमें किसी को शक नहीं कि भारत और पाकिस्तान की टीमों में हिमालय-सा अंतर आ चुका है। केवल क्रिकेट और स्किल की बात करें, तो कोई तुलना नहीं है। लेकिन, केवल क्रिकेट और स्किल की बात और टीमों के साथ होती है। भारत-पाकिस्तान मुकाबला दोनों देशों के इतिहास, तनाव, युद्ध की छाया और करोड़ों लोगों की उम्मीदों के बोझ तले खेला जाता है। यही वजह है कि फाइनल में एक वक्त भारतीय टीम भी प्रेशर में नजर आ रही थी।

बहस नहीं थमेगी । सुपर-4 में पाकिस्तान पर जीत के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा था - कैसी राइवलरी? जो टीम पिछले 39 T-20 मुकाबलों में से 36 जीत चुकी हो, उसके लिए किसी भी टीम के साथ कैसी राइवलरी! और यह टीम भी अभी पूरी बनी नहीं। यहां से टीम इंडिया नए लक्ष्य पर फोकस करेगी, गलतियों को सुधारने पर ध्यान देगी, लेकिन सवाल है कि यहां से एशियन क्रिकेट का रास्ता क्या होगा, खासकर भारत-पाकिस्तान का? इस टूर्नामेंट ने क्रिकेट डिप्लोमेसी की वह आड़ गिरा दी, जिसका सहारा लेकर दोनों पड़ोसियों के बीच खेल की वकालत की जाती है।

बनते-बिगड़ते रिश्ते । क्रिकेट डिप्लोमेसी शब्द का बढ़ा-चढ़ाकर इस्तेमाल उसी तरह किया गया, जैसे कि पाकिस्तानी टीम इंटेंट और स्ट्राइक रेट का करती है। 1987 में पाकिस्तान के तानाशाह मोहम्मद जिया-उल-हक ने इसकी शुरुआत की थी। भारत दौरे पर आई पाकिस्तानी टीम का एक टेस्ट मैच देखने के लिए जिया ने जयपुर पहुंच सबको चौंका दिया था। हालांकि कुछ ही वक्त बाद वही जिया पाकिस्तान के पास परमाणु बम होने की धमकी दे रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने भी कोशिश की थी। 1999 से 2012 के बीच तीन बार पाकिस्तानी टीम यहां आई और तीन बार भारतीय टीम वहां गई - पर इस बीच दोनों देशों के रिश्ते स्टॉप-स्टार्ट मोड में रहे। वजह - कारगिल, संसद पर हमला, मुंबई 26/11।

राजनीति से अलग नहीं । इतिहास में तमाम उदाहरण हैं और क्रिकेट में भी कि खेल और राजनीति कभी अलग नहीं रहे। दक्षिण अफ्रीका पर बैन लगना या हटना, जिम्बाब्वे का केस, ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान से न खेलना - ये सब बस खेल भर नहीं था। अगर सियासत न होती, तो मोहसिन नकवी PCB के अध्यक्ष भी न होते। इस एशिया कप ने बस यही किया कि इस भ्रम को दूर कर दिया है।

कांटे की बात

कच्चे तेल के आयात से करीब 22 लाख करोड़ रुपये देश से बाहर जा रहे थे। कुछ के कारोबार इससे प्रभावित हुए और वे मेरे खिलाफ पैसे देकर खबरें चलवाने लगे। मैंने किसी भी ठेकेदार से एक पैसा नहीं लिया है, जिससे वे मुझसे डरते हैं।

नितिन गडकरी, *पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण को लेकर लगे आरोपों पर*

छोटी सोच, बड़ा फ़र्क़

पर्सनैलिटी बताएगी, किसे मिलेगी कितनी उम्र

लंबी उम्र सिर्फ दवाओ, डॉक्टरों या डाइट पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि रोजमर्रा की आदतों से भी प्रभावित होती है। हाल की एक स्टडी बताती है कि व्यवस्थित ढंग से रहने, एक्टिव और दूसरों की मदद करने वाले अच्छे इंसान होने के साथ-साथ लंबा जीवन भी पाते हैं।

छोटी-छोटी बातों पर ध्यान

रिसर्च में 22 से अधिक वयस्क शामिल किए थे, चार बड़ी स्टडी हुई और अलग-अलग कैटिगरी में 6 से 28 साल तक लोगों पर नजर रखी गई। टीम ने पर्सनैलिटी की बारीक खूबियों पर ध्यान दिया, जैसे जीवन को लेकर जोश, जिम्मेदारी, मेहनत, बारीकी से काम करना, मदद करने का जज्बा और ऑर्गनाइज्ड रहना। इसमें सबसे अहम आदत निकल कर आई 'सक्रियता'।

आदतों की जांच

रिसर्चर्स के मुताबिक, अगर PERSONALITY SCREENING को स्वास्थ्य जांच का हिस्सा बनाया जाए, तो ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, जिन्हें अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए जीवनशैली सुधारने की जरूरत है। तीन दशक तक चली रिसर्च पर शोधकर्ताओं ने माना, सिर्फ स्वभाव से उम्र तय नहीं होती, यह एक अहम फैक्टर जरूर है। सकारात्मक आदतें लंबी जिंदगी की ओरले जा सकती हैं।

मीम बहार

पहाड़ की झीलें दे रहीं हादसे को न्योता

देश के हिमालयी राज्यों में इस बार मेघ कुछ ज्यादा ही बरस रहे हैं। समय से पहले बर्फबारी भी हो गई। हालांकि बर्फ गिरना ग्लेशियरों की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन मानव के लिए खतरे का संकेत है। केंद्रीय जल आयोग, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान और IIT रुड़की के वैज्ञानिकों की रिसर्च रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है। इसमें हिमालयी राज्यों में झीलों की संख्या और उनके आकार में बढ़ोतरी के बारे में बताया गया है। इन झीलों के कारण कभी भी कोई हादसा हो सकता है।

बृजेश सती

पिघल रहे ग्लेशियर । रिपोर्ट ऐसे समय आई है, जब देश के कई राज्यों खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बाढ़, भूस्खलन और अतिवृष्टि से भारी तबाही हुई। केंद्रीय जल आयोग (CWC) की रिपोर्ट बताती है कि जून 2025 तक देश में हिमनद झीलों का क्षेत्रफल लगभग 30% बढ़ गया है। यह 1917 हेक्टेयर से बढ़कर 2508 हेक्टेयर तक पहुंच गया है।

कॉमनरूम

AI Image

बढ़ रहा क्षेत्रफल । अगर राज्यवार देखें तो सबसे ज्यादा 197 झीलें अरुणाचल प्रदेश में हैं। इसके बाद लद्दाख में 120, जम्मू-कश्मीर में 57, सिक्किम में 47, हिमाचल प्रदेश में 6 और उत्तराखंड में 5 झीलें हैं। जून 2025 के दौरान 2843 हिमनद झीलों की निगरानी की गई। इसमें से 1435 के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। आकार बढ़ने से झीलों के फटने का खतरा बढ़ जाता है। निचले इलाकों की बस्तियों और इंफ्रा के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक है।

निगरानी की जरूरत । इसी तरह से वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में 1000 से अधिक हिमनद झीलें मौजूद हैं। उपग्रह चित्रों के आधार पर इनमें से 426 झीलों की पहचान की गई, जिनमें 25 को संभावित खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। इनमें से 6 सबसे अधिक खतरनाक (श्रेणी-1), 6 मध्यम खतरे वाली और 13 कम खतरे वाली मानी गई हैं। अलकनंदा घाटी में 9 और धौलीगंगा घाटी में 6 झीलें सबसे अधिक संवेदनशील पाई गई हैं। उत्तराखंड में खतरा तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इन झीलों की निरंतर निगरानी और जोखिम कम करने के लिए ठोस रणनीति बनाना जरूरी है।

प्रकृति का ख्याल । IIT रुड़की के वैज्ञानिक सवा सुब्रमण्यन और शिवानी जोशी की रिपोर्ट बताती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन से बनी झीलें गंभीर आपदा का रूप ले सकती हैं। जब भूस्खलन किसी नदी को रोक देता है तो वहां पानी जमा होकर झील बन जाती है और जब यह टूटती है तो भयानक तबाही लाती है। वाडिया संस्थान के डायरेक्टर डॉ. विनीत गहलोत का मानना है कि स्थानीय भूगोल को ध्यान में रखकर विकास कार्य करने की जरूरत है।

स्वयं शुद्ध और आनंदित होकर ही बांट सकते हैं ख़ुशी

जयति गोयल

नवरात्रि के आठवें दिन महागौरी की उपासना की जाती है। उनका उज्ज्वल स्वरूप निर्मलता, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। मान्यता है कि घोर तपस्या के बाद जब भगवान शिव ने गंगाजल से पार्वती का स्नान कराया, तब उनका रूप अत्यंत गौर हो गया और वह महागौरी कहलाईं।

हमारे यहां तो कहा भी जाता है – आठ वार और नौ त्योहार। सच सोचिए, यदि हमारे पर्व-त्योहार और परंपराएं न होते तो जीवन कितना नीरस और बेरंग होता। त्योहार आनंद और उत्सव के पर्याय हैं, जो हमें ईश्वर के निकट ले जाते हैं। तन-मन का प्रसन्न होना भी ईश्वर का आशीर्वाद है।

आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तनाव में महागौरी का स्वरूप हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर की कलुषता को त्यागें और सादगी व सच्चाई को अपनाएं। जब हम स्वयं शुद्ध और आनंदित होते हैं, तभी दूसरों के जीवन में भी उजियारा बांट पाते हैं। यही भाव हमारे सभी त्योहारों में समाया है। ये त्योहार रिश्तों की खाई को पाटते हैं, आपसी दूरी मिटाते हैं और संस्कृति से गहरा संबंध जोड़ते हैं। यही कारण है कि हमारी संस्कृति चिरपुरातन होकर भी सदैव चिरनवीन बनी रहती है।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

हर कोई मुस्कुराना चाहता है, पर इसके लिए आंतरिक खुशी आवश्यक है। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। त्योहार हमें खुशियां बांटने का अवसर प्रदान करते हैं। इनका धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। विशेष अवसर पर सुसज्जित और स्वच्छ घर देखकर हमारा मन प्रफुल्लित हो उठता है और निर्मल वातावरण में की गई पूजा-उपासना भी अधिक फलदायी होती है।

'उत्सव' शब्द ही बताता है – 'उत्' यानी उत्कृष्ट और 'सव' यानी यज्ञ। उत्सव दुख भूलकर आनंद मनाने का नाम है। वास्तव में उत्सव हम स्वयं बनाते हैं, और यदि चाहें तो हर दिन को उत्सव बना सकते हैं। परंपराएं जीवन को सहज और आनंदमय बनाने के लिए हैं, बोझ बनाने के लिए नहीं। त्योहार तभी सार्थक हैं जब उनके माध्यम से उल्लास का उजियारा हर कोने तक पहुंचे और हमारी सांस्कृतिक-धार्मिक परंपरा निरंतर प्रवाहित होती रहे।

जनता को लुभाएगी किसकी रेवड़ी

नरेंद्र नाथ

बिहार में NDA और I.N.D.I.A. के बीच विधानसभा चुनाव से पहले सियासी जंग तेज हो चुकी है। इसमें सबसे अहम है हमारी रेवड़ी बनाम उनकी रेवड़ी। एक तरफ तेजस्वी यादव की अगुआई में I.N.D.I.A. ने एक के बाद एक कई वादे किए, जिनमें महिलाओं को 2500 रुपये महीना का वादा भी शामिल है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA ने लगभग एक करोड़ महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपया देने के अलावा कई डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से जुड़े ऐलान कर दिए। अब उत्सुकता इस बात को लेकर है कि जनता किसकी रेवड़ी पर अधिक भरोसा करेगी और बिहार में इसका दूरगामी असर क्या होगा?

AI Image

विशुद्ध राजनीति

कसौटी

कभी BJP का मुद्दा थी रेवड़ी

दिलचस्प बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में BJP ने कभी रेवड़ी संस्कृति को बड़ा मुद्दा बनाया था और इस पर खूब राजनीति भी हुई थी। खुद पीएम मोदी ने सार्वजनिक मंच से इस रेवड़ी संस्कृति पर चिंता जताते हुए इसे रोकने की मांग की। लेकिन विपक्षी दलों ने कहा कि खुद केंद्र सरकार रेवड़ी देकर सत्ता में रहे, तो काउंटर करने के लिए उन्हें भी कुछ करना ही होगा। दरअसल, मुफ्त चीजें देने के राजनीतिक ट्रेंड ने सबसे पहले दक्षिण में अपना असर दिखाया था। 2006 में DMK ने वहां गरीबों को टीवी सेट और 2 रुपये किलो चावल देने का वादा किया था, जिसके बाद करुणानिधि सत्ता में आए। आगे चलकर जयललिता ने भी दो रुपये किलो चावल के जरिए अपनी जीत की राह खोली।

मुफ्त चीजें देने का राजनीतिक दबाव हाल के सालों में इतना बढ़ गया है कि राज्यों का बजट घाटा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम एक दर्जन राज्यों का बजट घाटा चिंताजनक स्तर पर जा चुका है, जहां अब तत्काल हस्तक्षेप करने की जरूरत हो सकती है। हालांकि तमाम राजनीतिक दल इसे भविष्य के लिए खतरनाक भी मानते हैं। लेकिन उनका तर्क है कि यह सभी पर एक समान लागू होना चाहिए। बिहार में एक सीनियर अधिकारी ने स्वीकार किया कि चुनाव के बाद बिहार को इन घोषणाओं के कारण बहुत गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।

कानूनी बहस भी शुरू

इस मसले पर कानूनी बहस भी पिछले कुछ सालों से लगातार हो रही है। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई हस्तक्षेप किए गए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग, दोनों ने राजनीतिक दलों के घोषणापत्र को कानूनी कवच देने और इसे अकाउंटेबल बनाने की पहल की है। लेकिन राजनीतिक दलों के प्रतिरोध के कारण इस दिशा में अभी तक वे एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सके हैं। आयोग ने सरकार के पास चुनाव सुधार से जुड़े जो प्रस्ताव भेजे, उसमें इस बारे में अपनी राय जाहिर कर दी थी। उस प्रस्ताव में था कि चुनावी घोषणापत्र को आदर्श आचार संहिता के दायरे में लाया जाएगा। यानी चुनाव से पहले 6 महीने की अवधि में कोई भी सरकार नई योजनाओं का ऐलान नहीं करेगी, और आयोग को घोषणापत्र पर स्पष्टीकरण लेने का अधिकार होगा। साथ में चुनाव आयोग मुफ्त बांटने वाली चुनावी घोषणा को वोटरों को प्रभावित करने की कैटिगरी में लाकर ऐसी घोषणा पर रोक लगा सकता है या फिर ऐसे घोषणापत्रों पर अंकुश लगा सकता है, जिसका पालन संभव न लग रहा हो और जिसका कोई आधार न हो। लेकिन किसी राजनीतिक दलों ने इस मसले पर मजबूत इच्छाशक्ति नहीं दिखाई।

रीडर्स मेल

भारत की रणनीति

29 सितंबर का संपादकीय 'विकल्पों की तलाश' भारत की विदेश नीति और वैश्विक व्यापार संतुलन की जटिलताओं को उजागर करता है। अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियों और ट्रंप की BRICS-विरोधी सोच ने सदस्य देशों के लिए चुनौतियां खड़ी की हैं। ऐसे में भारत का संतुलित दृष्टिकोण – एक ओर अमेरिका से संवाद बनाए रखना और दूसरी ओर BRICS जैसे मंचों के जरिए नए अवसर तलाशना – व्यावहारिक रणनीति है। डॉलर पर निर्भरता घटाने की आशंका अमेरिका को चिंतित जरूर करती है। बदलते हालात में विकल्पों की तलाश भारत की मजबूरी और दूरदर्शिता दोनों है।

गौरिका कपूर, ईमेल से

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 1 अंक 36

ग्रामीण ऋण में असमानता

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के ग्रामीण धारणा सर्वेक्षण, सितंबर 2025 में अन्य बातों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण में प्रगति और इसमें लगातार जारी खामियों का जिक्र किया गया है। इस सर्वेक्षण में एक सकारात्मक पहलू यह निकल कर आया है कि अब 54.5 फीसदी परिवार केवल औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जो 2024 में सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। मगर लगभग 22 फीसदी ग्रामीण परिवार अभी भी पूरी तरह अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त ऋणों पर निर्भर हैं। यह वर्ग अभी भी ऊंची ब्याज दर का भुगतान कर रहा है। औसत ब्याज दरें लगभग 17-18 फीसदी के आसपास हैं, जिनमें से एक तिहाई कर्जधारक सालाना 20 फीसदी से अधिक भुगतान करते हैं। लगभग 24 फीसदी परिवार औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तरह के ऋणों पर निर्भर हैं। इसके अलावा, लगभग 30 फीसदी परिवार अपने परिजनों एवं दोस्तों से ऋण लेते हैं जिन पर कोई ब्याज नहीं देना होता है। इस तरह, भले ही बैंक ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाने में सफल रहे हैं मगर ग्रामीण परिवारों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की 2024-25 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग शाखाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशेष रूप से गांवों में शाखाओं की संख्या मार्च 2010 के 33,378 से बढ़कर दिसंबर 2024 तक 56,579 हो गई। मगर अब भी कई परिवार साहूकारों पर निर्भर हैं जो यह संकेत दे रहा है कि केवल बैंकों की शाखाओं की संख्या बढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। ढांचागत व्यवस्था भी एक भूमिका निभाती है। कई ग्रामीण परिवारों को आय अस्थिरता, मौसमी जोखिमों और सरकार से घटते धन हस्तांतरण का सामना करना पड़ता है, जो अब मासिक आय का सिर्फ 9.27 फीसदी है। यह आंकड़ा सर्वेक्षण शुरू होने के बाद सबसे कम है। इन परिस्थितियों में भारी भरकम ब्याज के बावजूद अनौपचारिक ऋणों की तत्काल उपलब्धता और उनका लचीलापन अस्तित्व बनाए रखने की रणनीति के रूप में काम करते हैं।

सामाजिक और जनसांख्यिकीय कारक भी ऋण लेने के उद्देश्यों पर असर डालते हैं। नीति आयोग की 2025 की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 2019 से महिलाओं की तरफ से ऋणों की मांग 22 फीसदी चक्रवृद्धि दर से बढ़ रही है, जिनमें 60 फीसदी कर्जधारक कस्बाई एवं ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुक रखती हैं। कई लोग ऋण लेना तो चाहते हैं मगर इसके लिए उनकी तैयारी दुरुस्त नहीं होती, मसलन दस्तावेज की कमी, गारंटी दाता की कमी एवं अन्य शर्तें बाधा डाल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऋण असमानता दूर करने के लिए शाखा विस्तार के अलावा दूसरे कदम भी उठाने की जरूरत है। आगे की राह दोतरफा है। सबसे पहले, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण ढांचे को न केवल लक्ष्यों को बल्कि ऋण गुणवत्ता भी सुनिश्चित कर मजबूत बनाया जाना चाहिए। कमजोर वर्गों को होने वाले ऋण आवंटन पर नजर रखने और छोटे ऋणों, कम अवधि के ऋण वाली योजनाएं तैयार से साहूकारों पर निर्भरता कम होगी। इसके लिए बैंकों और सहकारी समितियों के लिए केंद्रित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है।

दूसरी बात, लागत कम करने और विश्वास बढ़ाने के लिए तकनीक का लाभ उठाया जा सकता है। 'आधार'-आधारित सूक्ष्म उधारी व्यवस्था, अंतर-परिचालन वाले डिजिटल वॉलेट और मोबाइल-आधारित शिकायत निवारण तंत्र यह अंतर पाट सकते हैं। बेहतर प्रोत्साहन और डिजिटल उपकरणों से लैस बैंक प्रतिनिधि ग्रामीण परिवारों और संस्थानों के बीच समन्वय का माध्यम बन सकते हैं। फिनटेक यानी वित्त-तकनीक कंपनियां कर्जधारकों के लिए विश्वसनीय क्रेडिट प्रोफाइल तैयार करने के लिए वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग डेटा का उपयोग कर सकती हैं। अंत में, नीति न केवल लोगों की बैंकों तक पहुंच सुनिश्चित प्रदान करने तक सीमित रहनी चाहिए बल्कि ऋण किफायती बनाने और वित्तीय जागरूकता में सुधार करने में भी मददगार होनी चाहिए। ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों से जुड़ी बुनियादी वित्तीय शिक्षा लोगों को साहूकारों पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद कर सकती है। ग्रामीण ऋण व्यवस्था ने अच्छी प्रगति की है लेकिन अनौपचारिक ऋणों की लागत और निर्भरता दर्शाती है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ग्रामीण भारत में ऋण असमानता दूर करना समावेशी विकास हासिल करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

आईटीसी के बिना जीएसटी का मकसद अधूरा

बेहतर इनपुट टैक्स क्रेडिट तंत्र की बहाली के बिना जीएसटी सुधार का एजेंडा अधूरा ही रहेगा। बता रहे हैं विजय केलकर, अरविंद मोदी और अजय शाह

अप्रत्यक्ष कराधान व्यवस्था अगर त्रुटिपूर्ण हो तो यह आर्थिक वृद्धि की राह में एक बड़ा रोड़ा बन जाता है। हम इस प्रणाली को दुरुस्त करने के शुरुआती प्रयासों का भी हिस्सा थे जब मूल्य वर्द्धित कर (वैट) की तरफ कदम बढ़ाया गया था जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक स्थापित अप्रत्यक्ष कर धारणा थी। वैट को हमने भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में पेश किया। इसका उद्देश्य एक स्वच्छ उपभोग कर बनाना है, जो उत्पादन के तरीकों या अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रति तटस्थ हो। यह किसी भी देश में अप्रत्यक्ष कराधान का सही तरीका है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) जीएसटी का एक दमदार प्रावधान है। व्यापक आईटीसी करों के अहितकारी प्रभावों को दूर करने के साथ यह भी सुनिश्चित करता है कि कर उत्पादन प्रत्येक स्तर केवल मूल्य वर्द्धन पर लगाया जाए। इससे यह तय होता है कि केवल उपभोग पर ही कर लगे जिससे एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार तैयार करने में मदद मिलती है।

मगर वर्तमान में जीएसटी इस प्रमुख सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यह प्रणाली एक ऐसा उदाहरण बन चुकी है जिसे लैंट प्रिचेट 'आइसोमॉर्फिक मिमिक्री' (समरूपी अनुकरण) कहते हैं, यानी इसने वैधता हासिल करने के लिए आधुनिक जीएसटी का बाहरी चोला पहन लिया है मगर अंतर्निहित लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहा है। आईटीसी ढांचे की राह में कानूनी एवं प्रक्रियात्मक उलझनें बाधा डाल रही हैं। कई मामलों में भारतीय जीएसटी पूर्व की उत्पाद एव सेवा कर प्रणाली की तरह उत्पादन पर लगाई जाने वाली कराधान व्यवस्था बन कर रह गई है।

जीएसटी की कार्य प्रणाली एक निर्बाध आईटीसी प्रणाली पर तैयार की गई है। जब कोई व्यवसाय अपने कच्चे माल (इनपुट) जैसे सामग्री, सेवाओं या पूंजीगत वस्तुओं पर कर भुगतान करता है तो उसे तुरंत पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। इससे सुनिश्चित होता है कि कर का लाभ संबंधित व्यक्ति तक आसानी से पहुंच जाए। आईटीसी रुकने से आर्थिक तर्क कमजोर हो जाता है। कर उपभोग के बजाय व्यवसाय या उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर लगना शुरू हो जाता है, जो आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से एक लागत के रूप में जुड़ जाता है। इससे कराधान का प्रभावी स्तर बहुत अधिक हो सकता है।

एक बाधा 'उलटे शुल्क संरचना' (इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर) के तहत रिफंड से जुड़ी है। यह समस्या तब सामने आती है जब इनपुट पर अंतिम उत्पादन की तुलना में अधिक दर पर कर लगाया जाता है। इस स्थिति में, अतिरिक्त क्रेडिट लौटाया जाना चाहिए (जैसा कि निर्यात के लिए शून्य-रेटिंग के साथ किया जाता है) लेकिन सीजीएसटी नियमों के प्रावधान 89(5) के अंतर्गत रिफंड भी केवल इनपुट वस्तुओं पर भुगतान किए गए कर तक ही सीमित है। इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर जमा आईटीसी नहीं लौटाया जाता है।

नॉमिनल जीएसटी दर और प्रभावी कर बोझ के बीच का अंतर अपना प्रभाव दिखाता है। 5 फीसदी कर श्रेणी में एक व्यवसाय के लिए आईटीसी रुकने का मतलब है कि कर भार नॉमिनल दर से अधिक है। एक माल आपूर्तिकर्ता को 14 फीसदी की प्रभावी दर का सामना करना पड़ सकता है जबकि एक सेवा प्रदाता का बोझ बढ़कर 28.4 फीसदी हो सकता है। इस रूप में जीएसटी एक आधुनिक उपभोग कर नहीं है बल्कि उत्पादन पर लगने वाले पुराने कर जैसा है।

वास्तविक वैट से इतर जाना एक सैद्धांतिक समस्या नहीं है बल्कि यह पूरी अर्थव्यवस्था को व्यापक एवं स्थायी क्षति पहुंचाता है और हमारे सबसे गतिशील क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यह नियम सेवाओं के क्षेत्र को असमान रूप से प्रभावित करता है। एक निर्माता अपने कच्चे माल पर रिफंड का दावा कर सकता है लेकिन उसे अब भी सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का संचय करना होगा। इसके उलट एक सॉफ्टवेयर या लॉजिस्टिक्स कंपनी (भले ही कानून में उसके साथ समान व्यवहार हो) को समान राहत नहीं मिलती है क्योंकि उनके इनपुट मुख्य रूप से अन्य सेवाएं और पूंजीगत साधन होते हैं। नतीजा यह होता है कि विनिर्माण एवं सेवा दोनों में लागत अधिक रहती है, लेकिन उन सेवाओं के मामले में बोझ और बढ़ जाता है जहां रिफंड प्रभावी रूप से सबसे अधिक अटके रहते हैं।

एक अव्यवस्थित क्रेडिट श्रृंखला में आयात के पक्ष में अधिक झुकाव है। एक घरेलू उत्पाद पर नॉमिनल 5 फीसदी जीएसटी लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी अंतिम तय कीमत में इसके इनपुट पर बिना क्रेडिट वाले करों के कारण बढ़ोतरी हो जाती है जिससे प्रभावी कर बोझ 14 फीसदी या उससे अधिक हो जाता है। हालांकि, सीमा पर ऐसे ही आयातित उत्पाद पर नॉमिनल दर पर कर लगाया जाता है। यह घरेलू उत्पादकों को एक संरचनात्मक नुकसान की स्थिति में पहुंचा देता है। सेवाओं के मामले में नुकसान अधिक होता है जहां इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं पर रुके क्रेडिट प्रभावी कर बोझ और अधिक बढ़ा देते हैं। इससे प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाती है।

जीएसटी निवेश पर लगने वाला कर बन कर रह गया है। पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए जीएसटी के लिए क्रेडिट अक्सर तब तक रोक दिया जाता है जब तक कोई परियोजना परिचालन शुरू नहीं करती और स्वयं अपनी कर देनदारी खड़ी नहीं करती है। लेकिन वर्तमान समय का 100 रुपये का क्रेडिट अगले तीन वर्षों में 100 रुपये के क्रेडिट से अधिक मूल्यवान हो जाता है। इस देरी से पूंजी की लागत बढ़ जाती है।

इस त्रुटिपूर्ण प्रणाली के बीच सितंबर 2025 में हुए 'जीएसटी 2.0' सुधारों ने कई चीजें और खराब कर दी हैं। 12 फीसदी कर श्रेणी को 5 फीसदी कर श्रेणी में विलय करने से कैस्केडिंग टैक्स के तहत आने वाली वस्तुओं का दायरा बढ़ गया है और प्रभावी उत्पादन कराधान अधिक हो गया है। जीएसटी के तहत निर्यातकों के लिए अंतर्निहित कराधान पूरी तरह से बेअसर नहीं हो पाता है, क्योंकि रिफंड में पूंजीगत वस्तुओं पर आईटीसी शामिल नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ व्यवहार पूर्ण रूप से शून्य-दर वाला निर्यात करना है ताकि हम कभी किसी विदेशी पर कर न लगाएं। लेकिन हमारे नियम विदेशी खरीदारों पर कर लगाने और भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बाधित करने की कोशिश करते हैं।

आईटीसी रुकावट का एमएसएमई पर कहीं अधिक असर पड़ता है। बड़ी कंपनियां रिफंड का प्रबंधन कर सकती हैं, आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन कर सकती हैं या वित्त पोषण से जुड़ी लागत अवशोषित कर सकती हैं। कम मार्जिन और कर्ज तक सीमित पहुंच के साथ काम करने वाले एमएसएमई में ऐसा लचीलापन नहीं है। उनकी लागत अधिक रहती है, उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता कम हो जाती है और उन्हें गहरे आयात पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। इस तरह, कर प्रणाली छोटी कंपनियों को असमान रूप से दंडित करती है।

पारंपरिक जीएसटी सुधार एजेंडे ने दो लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया है। पहला, व्यापक आधार के साथ एक एकल दर हासिल करना और आयात व निर्यात के साथ होने वाले व्यवहार में सुधार करना। अब एक तीसरी प्राथमिकता जोड़ी जानी चाहिए और वह है वास्तविक जीएसटी/वैट बनाने के लिए एक शुद्धतावादी इनपुट टैक्स क्रेडिट तंत्र की बहाली।

आगे के रास्ते के लिए तीन-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सबसे पहले कानून में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि सभी इनपुट-वस्तुओं, सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं में प्रवाह-आधारित, तत्काल और पूर्ण आईटीसी की गारंटी दी जा सके। दूसरा, एक बार क्रेडिट श्रृंखला तय हो जाने के बाद निचली दरों को ऊपर से मिलाकर लगभग 12-14 फीसदी के साथ राजस्व-तटस्थ दर में तब्दील कर दर संरचना को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए। अंत में, रिफंड से जुड़े कार्यों में सुधार की आवश्यकता है। वैट प्रणाली में रिफंड एक लगातार समस्या रही है मगर भारत के पास इससे निपटने की तकनीक है। सफल आयकर सीपीसी प्रारूप पर आधारित एक जीएसटी-सीपीसी (सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर) रिटर्न की प्रक्रिया को स्वचालित बना सकता है और जोखिम-आधारित जांच के आधार पर रिफंड जारी हो सकते हैं।

(लेखक पुणे इंटरनैशनल सेंटर और एक्सकेडीआर फोरम से संबद्ध हैं।)

ब्याज दर में कटौती के आसार बहुत कम

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने फरवरी और जून के बीच तीन किश्तों में नीतिगत रीपो दर में एक प्रतिशत अंक की कटौती के बाद, अगस्त महीने में दर को 5.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित छोड़ दिया था। इसके अलावा 'तटस्थ' मौद्रिक नीति रुख में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। ये दोनों फैसले आरबीआई की छह सदस्यीय दर-निर्धारण समिति में सर्वसम्मति से किए गए थे। जून में नीतिगत दर को आधा प्रतिशत कम करते समय, आरबीआई ने अपना रुख 'समायोजनकारी' से बदलकर 'तटस्थ' कर दिया था।

अगस्त महीने में, आरबीआई ने वर्ष 2025-26 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि अनुमान को भी 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा, लेकिन वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति दर के अपने अनुमान को घटा कर 3.7 से 3.1 प्रतिशत तक कर दिया। जून में, इसने इसे 4 प्रतिशत से घटाकर 3.7 प्रतिशत कर दिया था।

पिछली नीति की घोषणा करते हुए, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा था कि मौजूदा वृहद-आर्थिक परिस्थितियां, दृष्टिकोण और अनिश्चितताएं वास्तव में वर्तमान नीतिगत दर को बनाए रखने के संकेत दे रही हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पहले हुई बड़ी दर कटौती का ऋण बाजार और व्यापक अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है उसका इंतजार करना होगा ताकि पता चल सके कि इसका कितना फायदा हुआ है। इस वक्त अहम सवाल यह है कि अमेरिकी आयात शुल्क को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है ऐसे में हम 1 अक्टूबर के एमपीसी से क्या उम्मीदें कर सकते हैं?

इस पर बात करने से पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि पिछली नीति के बाद से क्या बदलाव आए हैं। सितंबर के मध्य में, अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने दिसंबर 2024 के बाद पहली बार अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में कटौती की और संकेत दिए कि इस साल और कटौती होने की संभावना है। वॉलस्ट्रीट की उम्मीदों के अनुरूप, उसने चौथाई प्रतिशत अंक की कटौती की, जिससे उसकी मुख्य ऋण दर के लिए लक्ष्य सीमा 4-4.25 प्रतिशत हो गई।

बैंकिंग साख
तमाल बंद्योपाध्याय

इस साल दो बार और चौथाई प्रतिशत अंक की कटौती की उम्मीद है, लेकिन फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आगे की कटौती 'पूर्व-निर्धारित तरीके से नहीं' होगी। यह इस तथ्य के बावजूद है कि 'जोखिमों का संतुलन' पहले के मुद्रास्फीति के पक्ष के बजाय, फेडरल रिजर्व के आदेश के मुताबिक रोजगार पक्ष की ओर स्थानांतरित हो गया है।

आरबीआई की पिछली मौद्रिक नीति के बाद, 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर यील्ड 9 आधार अंक बढ़कर 6.42 प्रतिशत हो गई क्योंकि बाजार ने नरमी के चक्र को खत्म होते देखा। यह रुझान अगस्त के अंतिम सप्ताह तक जारी रहा, जब 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड ने दिन के कारोबारी सत्र के दौरान 6.65 प्रतिशत के स्तर को छू लिया और 6.6 प्रतिशत पर बंद हुआ जो इस वित्त वर्ष में सबसे अधिक है। पिछले शुक्रवार को यह 6.5 प्रतिशत पर बंद हुआ।

पिछले सप्ताह जारी किए गए चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए 6.77 लाख करोड़ रुपये सकल सरकारी उधारी कैलेंडर का यील्ड पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। इसके अलावा, साप्ताहिक नीलामियों को फरवरी के बजाय मार्च तक बढ़ाना भी आपूर्ति के दबाव को कुछ हद तक कम करेगा।

इस बीच, रुपया जो पिछली नीति के दिन 87.73 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर कारोबार कर रहा था वह पिछले शुक्रवार को 88.72 रुपये पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह की शुरुआत में, इसने डॉलर के मुकाबले एक नए निचले स्तर को छुआ और 88.75 रुपये पर बंद होने से पहले दिन के कारोबारी सत्र के दौरान 88.80 रुपये के स्तर को छू लिया। इस समय कमजोर रुपया कोई बड़ी समस्या नहीं हो सकता क्योंकि व्यापार संघर्ष में कमजोर मुद्रा मददगार साबित होती है जब तक कि कच्चे तेल की कीमत न बढ़ जाए।

जून नीति से पहले, जब आरबीआई ने रीपो दर में आधा प्रतिशत अंक की कटौती की थी तब बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 1 प्रतिशत अंक कम करके अर्थव्यवस्था में 2.5 लाख करोड़ रुपये जारी किए थे (सितंबर के पहले सप्ताह और नवंबर के अंतिम सप्ताह के बीच)। साथ ही नीतिगत रुख को समायोजनकारी से तटस्थ में बदल दिया था, तब 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड 6.19 प्रतिशत थी और रुपया 85.63 प्रति डॉलर था।

जून में समाप्त तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से अधिक 7.8 प्रतिशत की तेज वार्षिक दर से बढ़ी जो इसकी पिछली तिमाही के 7.4 प्रतिशत से अधिक थी। इस वृद्धि ने कई अर्थशास्त्रियों को हैरान कर दिया। यह वृद्धि दरअसल विनिर्माण, निर्माण और सेवा क्षेत्रों में आई तेजी के कारण संभव हुई थी। खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में बढ़कर 2.07 प्रतिशत हो गई। यह जुलाई 2025 में 1.55 प्रतिशत थी, जो जून 2017 के बाद सबसे कम स्तर था और आरबीआई के 2-6 प्रतिशत के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य के दायरे के निचले सिरे से भी कम था।

अब सवाल यह है कि वृद्धि और मुद्रास्फीति पर क्या नजरिया है? भारतीय रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन का रुख सितंबर महीने में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आशावादी रहा। इसमें यह बताया गया कि खपत मांग में लगातार सुधार हो रही है और अधिक निवेश तथा मजबूत वृद्धि का एक 'बेहतर चक्र' बन सकता है जो 'लगातार बनी वैश्विक अनिश्चितताओं' की स्थिति से निपट लेगा। इसके अलावा इसमें वस्तु एवं सेवा कर में सुधारों की तारीफ की गई है जिन्हें खपत बढ़ाने, व्यापार को आसान बनाने और खुदरा कीमतों को कम करने वाला बताया गया है। इसके अलावा वृद्धि में मदद करने वाले अन्य कारकों में ब्याज दर में बड़ी कटौती का असर, आयकर में राहत और रोजगार बढ़ाने के उपाय हैं।

ऐसे आशावादी माहौल में आखिर दर कटौती की उम्मीद क्यों की जा रही है? शायद यह दीवाली का तोहफा हो, या शायद जो बेहतर स्थिति दिखाई जा रही है वह उतनी बेहतर न हो। एक चिंता का कारण यह है कि जून तिमाही में नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 8.8 फीसदी रही, जो पिछली तिमाही के 10.8 फीसदी से कम है। यह पिछले तीन तिमाही में सबसे कम है।

अब सवाल यह है कि क्या मौद्रिक नीति समिति अभी कटौती करेगी, या वह दिसंबर की अगली बैठक तक इंतजार करेगी? दिसंबर तक, आयात शुल्क की अनिश्चितताएं कम हो सकती हैं। तब वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े भी उपलब्ध होंगे और जीएसटी कटौती का मुद्रास्फीति पर पूरा असर दिख जाएगा। अगर आरबीआई इस सप्ताह दरों को यथावत रखता है तब नीतिगत रुख के 'नरम' रहने की उम्मीद है।

(लेखक जन स्मॉल फाइनैंस बैंक के वरिष्ठ सलाहकार हैं)

आपका पक्ष

भारत-ईयू एफटीए में हो टेक्नॉलजी पर जोर

इस समाचार पत्र में भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर प्रकाशित लेख तथ्यपरक है। यूरोपीय संघ के देशों की व्यापारिक आवश्यकताओं और टेक्नॉलजी के क्षेत्र में उनके एडवांटेज को समझकर अगर मुक्त व्यापार समझौता किया जाए तो भारत और यूरोपीय संघ दोनों को लाभ होगा। भविष्य में वैश्विक व्यापार में टेक्नॉलजी संबंधित समझौते ही भारत को शिखर पर स्थापित कर सकते हैं। यूरोपीय देशों में तापमान बहुत कम रहने से उनके डेटा सेंटर ही अमेरिका सहित सभी देशों को डेटा की आपूर्ति करते हैं। भारत में डेटा सेंटर स्थापित किए गए हैं परंतु यहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। इस पक्ष का भी मुक्त व्यापार समझौते में प्रावधान रखना चाहिए। अमेरिका में आव्रजन संबंधित नियमों की सख्ती के कारण हमारे विद्यार्थियों के लिए यूरोप के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश को भी इस समझौते में समाविष्ट होना चाहिए। पर्यटन को लेकर भारत और यूरोपीय देशों के बीच अपार संभावनाएं हैं, इसलिए भारतीयों के लिए वीजा नियमों में ढील दिया जाना चाहिए। भारत के नीति निर्धारकों को यूरोपीय संघ के देशों और भारत के प्रमुख व्यापार संगठनों, टेक्नॉलजी और सूचना प्रौद्योगिकी के शीर्ष उद्यमियों और निर्यातकों के साथ विचार-विमर्श करके मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना चाहिए।

विनोद जौहरी, दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयेन की फाइल फोटो

अमेरिकी वीजा शुल्क में बढ़ोतरी चुनौती और अवसर

एच1बी वीजा शुल्क वृद्धि से वैश्विक तकनीकी उद्योग में हलचल मच गई है। इसका सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ना तय है क्योंकि अमेरिका में कुल एच1बी वीजा धारकों में करीब 71 फीसदी भारतीय हैं। शुल्क वृद्धि के बाद कई कंपनियां विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने से पहले दो बार सोचेंगी। जिससे कई भारतीय प्रतिभाएं अमेरिका में काम करने के बजाय अपने देश में ही अवसर तलाशेंगी। जिससे एआई, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों के लिए अपार संभावनाएं हैं। लिहाजा यह शुल्क वृद्धि भारत के लिए अवसर भी है और चुनौती भी।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

दीर्घकालिक लाभदायक फैसला

एच1बी वीजा शुल्क वृद्धि भारत के लिए सकारात्मक व नकारात्मक दोनों है। नकारात्मक रूप से देखें तो भारतीय आईटी कंपनियों की लागत बढ़ेगी और पेशेवरों के लिए अमेरिका जाना कठिन होगा, जिससे रोजगार व विदेशी मुद्रा आय प्रभावित हो सकती है। सकारात्मक पक्ष यह है कि यह पलायन रोककर भारत को अपने प्रतिभाशाली युवाओं को देश में ही अवसर देने और स्वदेशी उद्योगों को सशक्त बनाने का अवसर देता है। कुल मिलाकर अल्पकालिक नुकसान अवश्य है, लेकिन दीर्घकाल में यह भारत को आत्मनिर्भर और नवाचार केंद्रित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में प्रेरित कर सकता है।

अमृतलाल मारू, इंदौर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

वियतनाम के थान्ह होआ में सोमवार को चक्रवात 'बुआलोई' तट से टकराया। इससे पहले रविवार को ही देश के मध्य और उत्तरी प्रांतों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका था।

दैनिक जागरण

करुणा और प्रसन्नता मनुष्य की आंतरिक संपत्ति हैं

एशिया कप की ट्राफी

एशिया कप में विजेता बनी भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और साथ ही एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख मोहसिन नक्वी के हाथों ट्राफी लेने से इन्कार करने पर वे जिस तरह उसे लेकर चलते बने, वह क्षुद्रता की पराकाष्ठा ही है। आखिर ऐसा करके उन्होंने क्या हासिल कर लिया? क्या उनकी इस हरकत से भारतीय टीम एशिया कप की विजेता नहीं रही या फिर खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान पर उसकी जीत का महत्व कम हो गया? इस सच के लिए किसी ट्राफी की दरकार नहीं हो सकती कि एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत से फाइनल समेत जो तीन मैच खेले, उन तीनों में उसे हार का ही सामना करना पड़ा। पीसीबी प्रमुख न सही, मोहसिन नक्वी को एशियाई क्रिकेट परिषद के मुखिया के रूप में बचकाना व्यवहार करने से बचना चाहिए था। जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पीसीबी प्रमुख को यह संदेश दे दिया था कि भारतीय टीम उनके हाथों ट्राफी नहीं लेगी तो फिर उन्हें ऐसा करने की जिद छोड़नी चाहिए थी। उन्हें इतनी समझ होनी चाहिए थी कि जब भारतीय क्रिकेटर उनके क्रिकेटरों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं तो उनके हाथों ट्राफी कैसे ले सकते हैं? आखिर ऐसा तो है नहीं कि अन्य कोई ट्राफी नहीं दे सकता था। लगता है उन्होंने खुद को पाकिस्तान के गृहमंत्री के रूप में ही देखा, न कि पीसीबी और एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख के रूप में। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि वे एशिया कप विजेता की ट्राफी अपने घर नहीं ले जा सकते। वह भारत की है और रहेगी।

मोहसिन नक्वी ने जैसी हरकत की, उसके खिलाफ बीसीसीआइ ने आइसीसी में शिकायत दर्ज कराने का जो फैसला किया है, उसका नतीजा जो भी हो, भारत को पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के मामले में अपनी लक्ष्मण रेखा नए सिरे से खींचने के साथ ही उसे स्पष्ट भी करने की जरूरत है, ताकि वैसे विवाद सामने न आएं, जैसे एशिया कप में देखने को मिले। इस संदर्भ में सबसे पहले तो यही तय करना होगा कि पाकिस्तान से किस स्तर पर कितना क्रिकेट खेलना है? यह ठीक है कि खेल मंत्रालय ने हाल में स्पष्ट किया कि भारत केवल बहुपक्षीय खेल मुकाबलों में ही उससे खेलेगा, लेकिन इस पर सोचा जाना चाहिए कि भविष्य में बहुपक्षीय आयोजनों में उससे कम से कम खेल संपर्क कैसे हो? चूंकि आज के युग में खेल को राजनीति से अलग नहीं रखा जा सकता और जब पाकिस्तान को हर स्तर पर अलग-थलग करना भारत की नीति है तो फिर क्या खेल को अलग रखा जा सकता है? इन प्रश्नों पर विचार करते समय इसकी भी अनदेखी न की जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का खेल स्तरीय नहीं रह गया है और दोनों देशों के बीच के मुकाबलों से वह रोमांच भी गायब हो गया है, जो पहले कभी होता था।

नागरिक चेतना का प्रश्न

अदालती कागजों पर पान की पीक से सनी अंगुलियों की छाप देखकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रकाश सिंह की एकल पीठ द्वारा व्यक्त नाराजगी और टिप्पणियां उचित ही हैं। पीठ ने पाया कि सुबह से उसके पास मुकदमों की जितनी फाइलें आई हैं, उनमें से 10 फाइलों के पन्नों पर अंगुलियों के ऐसे धब्बे हैं, जो प्रायः तब बनते हैं जब इन्हें पान या पान मसाला खाने के बाद लार में डूबी अंगुलियों से पलटा जाए। इस पर पीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि कोई पन्ना लार के इस्तेमाल के कारण लाल पाया जाता है, तो वह ऐसी फाइल स्वीकार न करे। पीठ ने टिप्पणी की है कि 'यह न केवल घृणित और निंदनीय है, बल्कि बुनियादी नागरिक चेतना की कमी भी दर्शाती है।' न्यायमूर्ति ने नागरिक चेतना के जिस प्रश्न को फलक पर उभारा है, उसके विस्तृत दायरे पर चिंतन की आवश्यकता है। आखिर क्यों नियम कानून का कोड़ा चले बिना हमारी नागरिक चेतना जाग्रत नहीं होती? अदालतें और सरकारी कार्यालय पान की पीक से लाल दीवारों के लिए बदनाम रहे हैं। हालांकि सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से स्थितियां बदली हैं। पान की लार से लाल फाइलें भी डिजिटलीकरण के दौर में कम हुई हैं, इसके बावजूद भी यदि किसी न्यायमूर्ति की नजर से एक दिन में 10 ऐसी फाइलें गुजर रही हैं तो यह गंभीर प्रश्न है।

आखिर क्यों नियम कानून का कोड़ा चले विना नागरिक चेतना जाग्रत नहीं होती? उत्तर प्रदेश के लोगों को भी यह सोचना चाहिए

विकसित भारत के अनुकूल बने पुलिस

प्रकाश सिंह

आर्थिक प्रगति के लिए अच्छी पुलिस व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है। विकसित भारत के लिए हमारी पुलिस को भी तो विकसित होना पड़ेगा

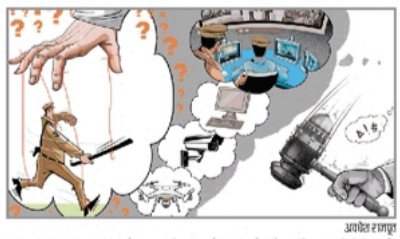

अवधेश राजपूत

इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में पुलिस हिरासत में मौतों के कुछ मामलों की सुनवाई चल रही है। ये मामले मध्य प्रदेश और राजस्थान के हैं। यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों का संज्ञान लिया, लेकिन और भी अच्छा होता कि वह पुलिस सुधार संबंधी 2006 के अपने आदेश के अनुपालन की वस्तुस्थिति भी देखे। 1996 में इन पंक्तियों के लेखक ने एक जनहित याचिका द्वारा पुलिस में सुधारों की मांग की। इसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की बहस के बाद 22 सितंबर, 2006 में तीन संस्थागत परिवर्तन के निर्देश दिए थे। एक, हर राज्य में एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन हो, जिसका मुख्य उद्देश्य पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त करना हो। दो, एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बने और इसके अंतर्गत पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के मामले में अधिकार हो, एक कंप्लेंट अथारिटी की स्थापना की जाए, जो पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर शिकायतों की जांच करे एवं महानिदेशक के चयन के लिए ऐसी प्रक्रिया बनाई जाए, जिससे केवल श्रेष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति उच्चतम पद पर हो सके और उनका कार्यकाल कम से कम दो वर्ष का हो। तीन, इन्वेस्टिगेशन और कानून एवं व्यवस्था के कार्य को बड़े शहरों में अलग-अलग किया जाए।

इस फैसले के बाद ऐसी आशा थी कि पुलिस विभाग को एक नई दिशा मिलेगी, पुलिस कर्मी देश के संविधान और कानून के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, जनता के प्रति उनका व्यवहार संवेदनशील हो जाएगा, शांति व्यवस्था में सुधार होगा, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। पुलिस सुधार पर सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला दिए 20 साल हो गए। उसके निर्देशों के अनुपालन में कुछ राज्यों में आदेश निर्गत किए गए और कुछ में एक नया अधिनियम बना दिया गया, परंतु बारीकी से देखा जाए तो पता चलता है कि उक्त आदेश और अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। नतीजा जमीनी स्तर पर हालात जस के तस हैं। कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है।

वास्तव में राज्य सरकारों को लगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश सही ढंग से लागू किए गए तो पुलिस उनके नियंत्रण से बाहर चली जाएगी और वे उसका जैसा उपयोग-दुरुपयोग करती हैं, वैसा नहीं कर पाएंगी। फलस्वरूप नेताओं और नौकरशाहों ने मन बना लिया कि वे इस आदेश का दिखावे के लिए तो पालन कर लेंगे, पर वास्तव में कोई परिवर्तन नहीं होगा और व्यवस्था जस की तस चलती रहेगी। जब देश आजाद हुआ था तो लोगों ने सोचा था कि पुलिस की मानसिकता और काम करने के तौर-तरीके में बदलाव आएगा। स्वतंत्रता के बाद पुलिस अधिकारियों की जो पौध आई, उसमें एक जज्बा और देशसेवा की भावना थी। इसलिए कुछ वर्षों तक तो पुलिस की गाड़ी ठीक चलती रही, परंतु जैसे-जैसे समय बीतता गया, पुलिस और नेताओं के बीच साठगांठ बढ़ती गई और दोनों एक-दूसरे के फायदे के लिए काम करने लगे। इसका वीभत्स स्वरूप हमें 1975 में इमरजेंसी के दौरान दिखा, जब पुलिस ने बहुत से ऐसे काम किए, जो उसे नहीं करने चाहिए थे। नेताओं के कहने पर फर्जी रिपोर्ट लिखी गई, लोगों को अकारण गिरफ्तार किया गया और तरह-तरह के अत्याचार हुए। बाद में शाह कमीशन द्वारा इनकी जांच हुई। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकनी है तो पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त करना पड़ेगा। इसी बीच 1977 में नेशनल पुलिस कमीशन का गठन हो गया। कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली का गहन परीक्षण किया गया और विस्तृत सुझाव दिए गए। कमीशन की रिपोर्ट जब तक आई, तब तक इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आ गईं और चूंकि यह रिपोर्ट उनके शासन के कार्यों के आधार पर बनी थी, इसलिए उसे दरकिनार कर दिया गया।

2008 में सुप्रीम कोर्ट ने थामस कमेटी का गठन किया था, यह देखने के लिए कि 2006 के उसके आदेश का किस हद तक पालन हुआ है। कमेटी ने पाया कि सभी राज्यों में इस आदेश के पालन में उदासीनता है। पुलिस सुधार की गाड़ी लड़खड़ाती हुई चल रही है। अपेक्षाएं बहुत थीं, पर परिवर्तन नाम मात्र के हुए। सवाल यह है कि भविष्य में क्या रणनीति अपनाई जाए। मेरे विचार से तीन काम करने की जरूरत है। एक तो यह कि पुलिस अधिकारी ऐसे आंतरिक सुधारों पर ध्यान दें, जिनके लिए सरकार से न तो स्वीकृति चाहिए और न ही धनराशि का आवंटन। इससे जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। जब कोई आदमी अस्पताल जाता है तो उसे यह विश्वास होता है कि वहां के इलाज से उसे कुछ न कुछ फायदा होगा। इसी तरह हर व्यक्ति जो थाने जाता है, उसे यह विश्वास होना चाहिए कि यहां मेरे कष्ट का निवारण होगा। इसके लिए पुलिस को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। रिपोर्ट लिखने में जो कोताही होती है, उसे खत्म करना पड़ेगा। दूसरा काम पुलिस के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार का हो। जनशक्ति में जो कमी है, उसकी पूर्ति की जाए। वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए, संचार व्यवस्था को और आधुनिक किया जाए। फोरेंसिक लैबोरेट्रीज की संख्या में वृद्धि हो, पुलिसकर्मियों की आवासीय सुविधा बेहतर हो। इससे पुलिस की कार्यक्रमता और मनोबल, दोनों बढ़ेंगे। तीसरा काम तकनीक के अधिकतम प्रयोग का होना चाहिए। सीसीटीएनएस चल पड़ा है, इससे पुलिस के काम में बहुत सुधार हुआ है। नेटग्रिड भी काम करने लगा है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए हमें बेहतर प्रशिक्षित स्टाफ तैयार करना पड़ेगा। साइबर अपराध पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जहां प्रयोग हो सके, किया जाए। जैसे-जैसे तकनीक का प्रयोग बढ़ेगा, पुलिस की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

पुलिस सुधार की जरूरत पर जितना भी लिखा जाए, कम होगा। लोकतांत्रिक ढांचे को स्वस्थ रखने के लिए पुलिस में परिवर्तन अनिवार्य है। आर्थिक प्रगति के लिए अच्छी पुलिस व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री बार-बार विकसित भारत की बात करते हैं, पर विकसित भारत के लिए पुलिस को भी तो विकसित होना पड़ेगा। यह विकास पुलिस में संस्थागत परिवर्तन के बिना नहीं हो पाएगा। आज की शासकीय पुलिस को हमें जनता की पुलिस के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा।

(लेखक उत्तर प्रदेश पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक हैं)

response@jagran.com

सुधार की मांग करती प्रवेश प्रक्रिया

प्रेमपाल शर्मा

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए होने वाले कामन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की समीक्षा की जानी चाहिए

दिल्ली विश्वविद्यालय के 30 प्रमुख कालेजों में ग्रेजुएशन की करीब नौ हजार सीटें अभी खाली हैं। जहां नियमित पढ़ाई की शुरुआत आमतौर पर जुलाई के मध्य में होती थी, वहीं इस वर्ष सितंबर के अंत तक भी दाखिला प्रक्रिया जारी है। पिछले वर्ष भी प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ियों के कारण दाखिले अक्टूबर में समाप्त हुए थे। ऐसे में छात्रों को पढ़ाई के लिए समय कब मिलेगा? अक्टूबर का महीना दशहरा, दीवाली और छठ जैसे त्योहारों में व्यतीत होगा तथा दिसंबर के अंत में क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां भी आ जाएंगी। विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए चार साल पहले एक कामन प्रवेश परीक्षा की शुरुआत की गई थी। इस प्रवेश परीक्षा का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव गांव के गरीब बच्चों पर पड़ा। वे आनलाइन परीक्षा कंप्यूटर पर देने के लिए उतने अभ्यस्त नहीं होते। इसके अलावा उन्हें जो विषय पढ़ाए गए हैं, परीक्षा में उनसे अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए शहरों में कोचिंग का धंधा तेजी से फैल रहा है। इसका परिणाम यह है कि पिछले चार वर्षों में लड़कियों के दाखिले की संख्या में कमी आई है। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले बच्चों की संख्या में भी गिरावट आई है। किसी भी अच्छे विश्वविद्यालय के लिए यह अच्छे संकेत नहीं हैं, विशेषकर केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए। इसका और भी बुरा परिणाम यह है कि बच्चों को अपनी रुचि के विषय में दाखिला नहीं मिल पा रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रमुख कालेजों में कंप्यूटर, विज्ञान, गणित जैसे विषयों में भी सीटें खाली हैं, जो आश्चर्यजनक है। हिंदी और संस्कृत जैसे विषयों में दाखिले का हाल तो अतीत में भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन वर्तमान में इसमें इतनी गिरावट आई है कि कहीं ये विभाग बंद न करने पड़ जाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय समेत अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हिंदी और संस्कृत जैसे विषयों को पढ़ने के लिए बच्चे आगे नहीं आ रहे हैं। सरकार ने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, फिर भी समाज में अपनी भाषाओं में पढ़ने के प्रति उत्साह नहीं लौट रहा है। छात्रों को यह बताने की आवश्यकता है कि अब अपनी भाषा के

छात्रों की समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता। फाइल

माध्यम से वे केंद्र समेत राज्यों की सभी नौकरियों में आसानी से भर्ती हो सकते हैं, लेकिन छात्र अब भी अंग्रेजी की ओर दौड़ रहे हैं। उनके मन में यह बैठ गया है कि भले ही सरकार कितने भी प्रयास करे, हिंदी और संस्कृत पढ़ने से नौकरी नहीं मिलेगी। सीटें खाली रहने का एक और कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कालेजों में फीस कई गुना बढ़ गई है। इससे विद्यार्थियों को लगता है कि फिर बीबीए, एमसीए जैसे व्यावसायिक कोर्स अपने गांव के आसपास क्यों न किए जाएं?

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक कामन प्रवेश परीक्षा से दाखिले का विचार इसलिए आया था, क्योंकि अलग-अलग राज्यों में 12वीं के अंकों का प्रतिशत समान नहीं होने से विद्यार्थियों को अलग-अलग विश्वविद्यालयों में भागना पड़ता था, लेकिन इसका विकल्प जो आया, उसने स्थितियों को और खराब कर दिया है। जो दाखिले की प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरी होकर पढ़ाई शुरू हो जाती थी, अब उस विलंब के कारण बच्चे निराश होकर निजी विश्वविद्यालयों की ओर भाग रहे हैं, जहां फीस कई गुना अधिक है। कोचिंग का धंधा भी इससे बढ़ा है। नई शिक्षा नीति बार-बार रटने पर लगाम की बात करती है, लेकिन इस प्रवेश परीक्षा में तो रटना और भी अनिवार्य हो गया है। अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के देशों में प्रारंभिक शिक्षा में कम्युनिकेशन पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। यानी वहां बच्चों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाना सबसे जरूरी है। नई प्रवेश परीक्षा में जहां मल्टीपल च्वाइस प्रश्न होते हैं, वहां उत्तर लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज जब अमेरिकी राष्ट्रपति वीजा फीस बढ़ाने से लेकर भारतीय विद्यार्थियों के लिए नई-नई मुसीबतें पैदा कर रहे हैं, तब हमें तुरंत ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे हमारी युवा पीढ़ी निराश न हो। विश्वविद्यालयों का उद्देश्य उनकी रचनात्मकता को बढ़ाना होना चाहिए, न कि रोकना। चार वर्षीय स्नातक प्रोग्राम के चौथे वर्ष में हर विषय में सीटें खाली हैं। इससे शोध की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी।

पिछले वर्षों में सीटें खाली रहने के कारण देश के कई राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में कई इंजीनियरिंग कालेज बंद करने पड़े हैं। दिल्ली में करीब एक दर्जन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, जिन पर प्रति विद्यार्थी खर्च भी देश में सबसे ज्यादा आता है। इस समय दुनिया का ज्ञान सर्वत्र सुलभ है। हमारी युवा पीढ़ी बहुत मेहनती है। यह दुनिया के सभी देश कहते हैं और इसका प्रमाण भी है। दिल्ली केवल राजनीति और सत्ता का केंद्र नहीं है, बल्कि शिक्षा एवं संस्कृति का भी उभरता केंद्र है। इसलिए दाखिले की प्रक्रिया से लेकर शिक्षा, पाठ्यक्रम तक सभी पहलुओं पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा यह उक्ति चरितार्थ होगी कि भारतीय विश्वविद्यालय तो बस तीन काम करते हैं- एडमिशन, इलेक्शन और एग्जामिनेशन! हमें शिक्षा नीति में इन पहलुओं पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

(भारत सरकार में संयुक्त सचिव रहे लेखक शिक्षाविद् हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आत्मबल

मनुष्य को पूजा-पाठ जीवन को नियमित, व्यवस्थित तथा संयमित करने के लिए करना चाहिए, न कि किसी चमत्कार के लिए। बहुत से लोग यह कहते सुने जाते हैं कि बहुत दिनों से धार्मिक कार्य कर रहे हैं, ताकि भगवान प्रकट हो जाएं और उनकी समस्या का समाधान कर दें। धर्मग्रंथों की कथाओं पर अगर ध्यान दिया जाए तो इस तरह की भ्रांति नहीं होगी। जप-तप से मन में बैठी नकारात्मकता दूर होती है, आत्मबल मजबूत होता है। यदि सच कहा जाए तो आत्मबल ही भगवान है। आत्मबल सत्य-आचरण से ही संभव है। जबकि गलत कामों से भय उत्पन्न होता है। भय व्यक्ति को इतना कमजोर बना देता है कि वह हमेशा संशय तथा उलझन में रहता है। इस स्थिति में दिमाग डांवाडोल हालत में रहता है। फिर कोई काम सुचारु रूप से नहीं हो पाता है। यहां तक पूजा-पाठ भी बेमन से होता है। जीवनचर्या बाधित होती है।

तुलसीदास ने 'दीनदयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी' चौपाई में पद, संपत्ति, आजीविका के संकट हरने के लिए नहीं, बल्कि काम-क्रोध-मद-लोभ आदि जो मन को संकट में डालते हैं, उनको हरने की ओर इंगित किया है। जिस प्रकार से बादलों से घिरे सूरज से प्रकाश नहीं मिलता, उसी प्रकार दुर्गुणों से घिरे मन से ऊर्जावान विचार नहीं जन्म लेते। जब संकल्प ही कमजोर होगा, तब कार्य उसी प्रकार कमजोर होगा, जैसे नींव कमजोर होने पर भवन मजबूत नहीं बन सकता। भगवान की पूजा करते समय उन सद्गुणों को अपनाने पर जोर देना चाहिए, जो मनुष्य से देवता बनाने की राह पर ले जाएं। हालात को कोसने के बजाय हर स्थिति में हंसते-मुस्कुराते जीवन जीना चाहिए, क्योंकि दुखी हालत में काम बनने के बजाय और बिगड़ जाता है। दयनीय स्थिति में लोग भी साथ देना तो दूर मजाक ही उड़ाते हैं।

सलिल पांडेय

संपत्ति में स्त्रियों की हिस्सेदारी

डा. मोनिका शर्मा

श्रम शक्ति में भागीदारी निभाने के बावजूद अधिकतर घरेलू महिलाएं संपत्ति के अधिकार से वंचित हैं

हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्त्री शक्ति के महत्व को समझाने वाला एक अहम निर्णय दिया। न्यायालय द्वारा परिवारों में गृहिणियों के योगदान को मान्यता देने की वकालत की गई। दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार अब समय आ गया है कि घर-परिवार संभाल रही स्त्रियों की भूमिका को संपत्ति के स्वामित्व संबंधी अधिकारों के संदर्भ में मान्यता दी जाए, क्योंकि घर बनाने और चलाने में गृहिणियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। असल में यह निर्णय स्त्री शक्ति के उस रूप की ओर ध्यान दिलाता है, जिसकी भागीदारी बहुधा अनदेखी रह जाती है। ध्यातव्य है कि एक महिला द्वारा उच्च न्यायालय से मांग की गई थी कि विवादित संपत्ति में उसका भी समान और वैध अधिकार घोषित किया जाए। महिला की ओर से कहा गया था कि उसने परिवार की देखभाल के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। उसे उसका हिस्सा न मिलना एक तरह का अन्याय ही होगा। न्यायालय की यह टिप्पणी घरेलू महिलाओं की भूमिका की गरिमा समझने की बात लिए है। आंगन तक सिमटी इस भागीदारी के मूल्य को समझकर सम्मान देने का आह्वान करती है।

वस्तुतः श्रम शक्ति में भागीदारी निभाने के बावजूद अधिकतर घरेलू महिलाएं संपत्ति के अधिकार से वंचित हैं। कोर्ट ने भी कहा है कि घरों में पूर्णकालिक गृहिणियों की मौजूदगी से विशेष मदद मिलती है। साथ ही हमारे देश के बहुत से परिवारों में घरेलू सहायक भी नहीं हैं। स्पष्ट है कि इन परिवारों में गृहिणियों की मौजूदगी बहुत से खर्चों को बचाती है। घर के रखरखाव और परिवारजनों की देखभाल वाले काम स्वयं करने से होने वाली बचत परिवार को संपत्ति खरीदने की स्थिति तक लाती है। महिलाओं की इस बचत से कई परिवार अपना घर बना पाते हैं। बहुत सी सुख-सुविधाएं जुटा पाते हैं। गौरतलब है कि देश में गृहिणियों द्वारा की गई बचत समूची बचत का 24 प्रतिशत है। बचत की यह भागीदारी दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। साथ ही उनके स्नेह, सहयोग और संबल का आर्थिक मोल आंकना तो असंभव ही है। ऐसे में पारिवारिक संपत्ति में गृहिणियों के स्वामित्व को लेकर सोचा जाना आवश्यक है।

असल में आर्थिक भागीदारी की अनदेखी से बहुत सी गृहिणियों में एक असुरक्षा की भावना बनी रहती है। ऐसे में आर्थिक हिस्सेदारी के महत्व को समझे बिना सुरक्षा और सम्मान का परिवेश भी नहीं बनाया जा सकता। महिलाओं की एक बड़ी आबादी को उपेक्षा के घेरे से निकालने के लिए उनके योगदान को समझना ही होगा। घरेलू महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक भागीदारी की अनदेखी को रोकने के लिए संपत्ति स्वामित्व में उनके अधिकारों को रेखांकित किया जाना बहुत आवश्यक है।

(लेखिका सामाजिक मामलों की जानकार हैं)

मेलबाक्स

भीड़ प्रबंधन का अभाव

संपादकीय 'भगदड़ का सिलसिला' में तमिलनाडु के करूर की घटना में 40 लोगों की मौत के जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने, भगदड़ की घटनाओं से सबक सीखने और प्रशासन की सुस्ती-लापरवाही को उजागर करने के साथ व्यवस्था पर निशाना साधा गया है। आखिर कब तक खास लोगों के आम प्रशंसक भगदड़ के शिकार होकर जिंदगी खोते रहेंगे? शासन-प्रशासन, कानून और व्यवस्था सभी मिलकर भी भगदड़ की घटनाओं को क्यों नहीं रोक पा रहे? उनकी नाकामी का खामियाजा लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं और जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होने से घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। इस तरह की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी ऐसी दुखद घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन कोई भी उनसे सबक सीखने को तैयार नहीं। भीड़ के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली और जवाबदेह तंत्र निर्मित करना अत्यावश्यक हो गया है, अन्यथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना मुश्किल होगा। प्रशंसकों और भीड़ का हिस्सा बनने वाले लोगों को भीड़ में किस तरह व्यवहार करना है, यह भी सिखाया जाना चाहिए। भगदड़ की अपरिहार्य स्थिति में कैसे बचें, इसके प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। आमतौर पर सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेल के बड़े आयोजनों में भीड़ जुटती है। ऐसे में आयोजनकर्ता को जगह की उपलब्धता और पर्याप्त सुविधा के अनुसार ही भीड़ को कार्यक्रम में शामिल होने हेतु बुलाना चाहिए और भीड़ के प्रबंधन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। जरा सी सावधानी कितने लोगों की जान बचा सकती है और जरा सी लापरवाही या चूक कैसे लोगों की मौत का कारण बन सकती है, ये घटनाएं इस बात का जीवंत उदाहरण हैं। इनसे सबक सीखा ही जाना चाहिए।

sonimohit895@gmail.com

सबसे बड़ी कुर्सी

आजकल बिहार की राजनीति में लालू यादव के परिवार में राजनीतिक कशमकश चल रही है। भारत की राजनीति में यह कहावत लागू होती है कि ''बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ी कुर्सी।'' कुछ राजनेता हवा के रुख के अनुसार अपना पाला बदल लेते हैं। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि जो लोग पाला बदल रहे हैं, उनके पीछे केवल स्वार्थ हो। पार्टी हाईकमान की गलत नीतियां और राज्य सरकार की अनदेखी भी इस स्थिति का कारण हो सकती हैं। लालू परिवार में चल रही राजनीतिक उठापटक से यह स्पष्ट होता है कि परिवारवाद की राजनीति लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। राजा-महाराजाओं की कहानियों में राजगद्दी पाने के लिए रिश्तेदारों के बीच संघर्ष होता था, लेकिन अब लोकतंत्र में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। चुनाव से पहले पार्टी के भीतर अंतर्कलह हमेशा नुकसानदायक होती है। राजेश कुमार चौहान, जालंधर

उत्तराधिकार की लड़ाई

उमेश चतुर्वेदी के लेख ''पारिवारिक दलों में विरासत की तकरार'' में यह बात सही है कि पारिवारिक दलों में वर्चस्व की लड़ाई तब तेज होती है जब पार्टी का पुरोधा कमजोर पड़ता है। इसका उदाहरण राजद और अन्य क्षेत्रीय दलों में स्पष्ट देखा जा सकता है। भारत के लोकतंत्र की विडंबना यह है कि कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल परिवारवाद के दायरे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। राजनीतिक दलों में कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास पर आधारित नेतृत्व के बजाय पारिवारिक उत्तराधिकार को प्राथमिकता दी जाती है। जब किसी दल के शीर्ष नेता की स्थिति कमजोर होती है, तो पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष और वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। लोकतंत्र की खूबसूरती समान अवसर और योग्य नेतृत्व में निहित है। लेकिन पारिवारिक और वंशवादी राजनीति इस मूल भावना पर आघात करती है। आज भी वही स्थिति देखने को मिल रही है जो कभी रजवाड़ों और सामंती व्यवस्था में होती थी। उस समय भी उत्तराधिकार और विरासत की लड़ाइयां होती थीं। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में आवश्यक है कि राजनीतिक दल परिवारवाद से ऊपर उठकर योग्य नेतृत्व को बढ़ावा दें।

sureshgoyal8@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सैक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

17.78 प्रतिशत वैश्विक जनसंख्या भारत में बसती है, जबकि वर्तमान में देश की आबादी 146.6 करोड़ है, जनसंख्या रिपोर्ट से संबंधित एक वैश्विक संगठन की वेबसाइट के अनुसार।

आजकल

भारतीय प्रतिभाओं की पसंद बन रहा जर्मनी

सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता पाने के लिए आज हर देश उच्च-स्तरीय तकनीकी प्रतिभा की तलाश कर रहा है। इस वैश्विक दौड़ में भारतीय आइटी विशेषज्ञों की मांग सबसे ज्यादा है। भारत में हर वर्ष लाखों इंजीनियर और तकनीकी स्नातक तैयार होते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में अमेरिका भी जाते रहे हैं। परंतु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई वीजा नीति के बाद अमेरिका जाने से जुड़ी मुश्किलों के कारण युवाओं का रुझान अन्य देशों की ओर हो रहा है। वैसे बीते कुछ वर्षों से बड़ी संख्या में भारतीय युवा जर्मनी भी जा रहे हैं, जिनकी संख्या अब और बढ़ सकती है

ब्रह्मदीप अलूने
सामाजिक-आर्थिक मामलों के जानकार

जर्मनी में वर्तमान में 60 हजार से अधिक भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे हैं। फाइल

अमेरिका की डिजिटल अर्थव्यवस्था केवल आर्थिक समृद्धि का आधार नहीं है, बल्कि यह वैश्विक तकनीकी नेतृत्व और रणनीतिक प्रभाव का प्रमुख स्तंभ भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वीजा प्रक्रिया को जटिल बनाकर भारतीय प्रतिभाओं को अमेरिका आने से रोकने की कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव अमेरिका पर भी पड़ सकता है। इन सबके बीच जर्मनी भारतीय आइटी विशेषज्ञों और विद्यार्थियों की स्वाभाविक पसंद हो सकता है।

वस्तुतः यूरोप की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल जर्मनी का अमेरिका पर भरोसा कम हुआ है तथा वह साफ्टवेयर विकास, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में अग्रणी बनकर अमेरिका पर से निर्भरता कम करना चाहता है। गूगल, माइक्रोसाफ्ट, अमेजन, एपल, मेटा जैसी कंपनियां अमेरिकी डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ये कंपनियां क्लाउड कंप्यूटिंग, ई-कामर्स, इंटरनेट मीडिया, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में अग्रणी हैं और वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानकों को निर्धारित करती हैं।

लागत और गुणवत्ता का अनूठा संतुलन भारतीय पेशेवरों को और भी प्रासंगिक बनाता है। विकसित देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम लागत पर उच्च-स्तरीय सेवाएं उपलब्ध होना कंपनियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। अंग्रेजी भाषा में दक्षता और बहुराष्ट्रीय अनुभव भारतीय आइटी पेशेवरों को वैश्विक टीमों के साथ सहजता से जोड़ देता है। भारतीयों की नवाचार और नेतृत्व क्षमता ने उनकी छवि को और मजबूत किया है। गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसाफ्ट के सत्य नडेला और एडोब के शांतनु नारायण जैसे पेशेवरों ने यह सिद्ध किया है कि भारतीय आइटी विशेषज्ञ वैश्विक स्तर पर दूरदर्शी नेतृत्व देने में भी सक्षम हैं।

यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्था : जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसकी वैश्विक पहचान न केवल औद्योगिक और तकनीकी ताकत से है, बल्कि इसके विश्वस्तरीय कंपनियों से भी है। जर्मनी में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो आटोमोबाइल, साफ्टवेयर, रसायन, बैंकिंग और खेल उद्योग में अग्रणी हैं। हाल ही में जर्मनी के विदेश मंत्री भारत आए तो उनकी यात्रा के केंद्र में भारत और जर्मनी के बीच प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग रहा। अपनी यात्रा की शुरुआत में ही वेडफुल ने फोकस स्पष्ट करते हुए भारत के साथ सुरक्षा, हथियारों में सहयोग और आर्थिक संबंधों का दायरा बढ़ाने की बात कही थी। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत बेंगलुरु से करते हुए प्रमुख नवाचार और प्रौद्योगिकी केंद्रों का दौरा किया था। इन कार्यक्रमों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे प्रमुख भारतीय संस्थानों के साथ बैठकें शामिल थीं। वेडफुल ने हरित प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, एआइ, अंतरिक्ष सहयोग और सतत शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी प्रकाश डाला। जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है तथा भारत में नौवां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी है। भारतीय शोधकर्ता मैक्स प्लैंक सोसायटी जैसे शीर्ष जर्मन संस्थानों में काम करते हैं। जर्मनी में 60 हजार से अधिक भारतीय अध्ययन कर रहे हैं, जो विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा समूह भी है।

वैश्विक स्तर की जर्मन कंपनियां : एसएपी एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय साफ्टवेयर कंपनी है। यह विश्वभर में एंटरप्राइज साफ्टवेयर समाधान प्रदान करने में अग्रणी है। यह हजारों पेशेवरों को स्थायी और उच्च-कौशल वाले रोजगार प्रदान करता है। भारतीय आइटी विशेषज्ञों के लिए एसएपी एक महत्वपूर्ण पसंद है। कंपनी में क्लाउड, एआइ, डाटा एनालिटिक्स और साफ्टवेयर विकास जैसे क्षेत्रों में काम करने के अवसर उपलब्ध हैं। वैश्विक परियोजनाओं और बहु-सांस्कृतिक टीमों के साथ काम करने की क्षमता वाले भारतीय पेशेवर एसएपी के लिए आकर्षक प्रतिभा स्रोत बनते हैं। फाक्सवैगन जर्मनी की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है। मर्सिडीज बेंज और बीएमडब्ल्यू ग्रुप लक्जरी और स्पोर्ट्स कारों के क्षेत्र में विश्वविख्यात हैं। ये कंपनियां जर्मनी की आटोमोबाइल तकनीक और नवाचार की पहचान हैं। इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में सीमेंस एजी औद्योगिक आटोमेशन, ऊर्जा, स्वास्थ्य उपकरण और स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जानी जाती है। वहीं, सैप एसई एंटरप्राइज साफ्टवेयर, क्लाउड सेवाएं और डाटा एनालिटिक्स में वैश्विक नेता है।

भारतीय आइटी विशेषज्ञों के लिए यह एक प्रमुख अवसर प्रदान करता है। खेल और लाइफस्टाइल उत्पादों में एडिडास एजी की वैश्विक पहचान है, जबकि कांटिनेंटल एजी, आटोमोटिव तकनीक में प्रसिद्ध है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रानिक्स में इंफिनियन टेक्नोलाजीज अग्रणी कंपनी है। जर्मनी की ये प्रमुख कंपनियां तकनीकी नवाचार, उच्च गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की पहचान हैं। भारतीय आइटी विशेषज्ञों के लिए ये कंपनियां अवसरों का केंद्र हैं, जहां वे डिजिटल, साफ्टवेयर और तकनीकी परियोजनाओं में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। ट्रंप की वीजा को लेकर भारत विरोधी नीतियों के बाद जर्मनी में भारत का प्रभाव बढ़ने की उम्मीद है। कारों से लेकर लाजिस्टिक्स तक, जर्मन कंपनियों को भारत के विकास की संभावनाओं से बड़ी उम्मीद है। वे कुशल युवाओं की बड़ी संख्या, सस्ती लागत और लगभग सात प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर का फायदा उठाना चाहती हैं। पिछले कुछ वर्षों में जर्मनी और भारत के बीच व्यापार ने एक नया रिकार्ड बनाया है। भारत को दशक के अंत तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर मजबूती से कदम बढ़ाने हैं।

आइटी विशेषज्ञों की व्यापक मांग के साथ जर्मनी फलता-फूलता तकनीकी उद्योग है। ब्लू कार्ड वीजा कार्यक्रम कुशल श्रमिकों के लिए यहां बसना आसान बनाता है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की तुलना में जर्मनी में जीवन-यापन की कम लागत तथा प्रतिस्पर्धी वेतन और उत्कृष्ट सामाजिक सुरक्षा लाभ भी है।

कई मामलों पर दोनों देशों के दृष्टिकोण में सामंजस्य

भारत और जर्मनी के द्विपक्षीय संबंध राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक क्षेत्रों में गहराई एवं विविधता लिए हुए हैं। दोनों देशों ने आपसी सहयोग को मजबूत बनाने के लिए समय-समय पर रणनीतिक समझौते और साझेदारियां स्थापित की हैं। जर्मन कंपनियां भारत में औद्योगिक उत्पादन, आटोमोबाइल, मशीनरी और ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं। इसके साथ ही भारत उच्च-कौशल आइटी सेवाओं, फार्मास्युटिकल्स और इंजीनियरिंग समाधानों के माध्यम से जर्मनी के बाजार में योगदान देता है। जर्मनी और भारत सामरिक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी रणनीतियों में सहयोग करते हैं। तकनीकी साझेदारी, साइबर सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के मामलों में दोनों देशों के दृष्टिकोण में सामंजस्य है।

इसके अलावा, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों देशों का सहयोग रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक सहयोग वैश्विक मंचों पर भी देखा जा सकता है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, जी-20 और विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर समान विचारधारा और लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करते हैं। औद्योगिक नवाचार, स्मार्ट सिटी, हरित ऊर्जा और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में दीर्घकालिक साझेदारी दोनों देशों के लिए रणनीतिक महत्व रखती है। भारत-जर्मनी सहयोग बहुआयामी और रणनीतिक है। आर्थिक, सामरिक और तकनीकी साझेदारी के माध्यम से यह दोनों देशों के लिए लाभकारी होने के साथ-साथ यूरोप और एशिया में स्थिरता, विकास और नवाचार का एक मजबूत आधार तैयार करती है।

जर्मनी भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार के रूप में देख रहा है, जिससे वे अपनी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकें और वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। चीन पर अपनी निर्भरता कम करने, अपने व्यापारिक हितों में विविधता लाने और अपनी आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए जर्मनी भारत के साथ संतुलन बनाना चाहता है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण बाजार है। भारत की बड़ी आबादी, उच्च-कुशल कामगारों की उपलब्धता और रणनीतिक स्थान इसे चीन के अलावा एक महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार बनाते हैं।

जर्मनी भारत को स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, निर्माण और सार्वजनिक परिवहन जैसे क्षेत्रों में लाखों रिक्तियों को भरने के लिए एक प्रमुख स्रोत मानता है। जर्मनी जर्मन भाषा प्रशिक्षण को मजबूत करने और अधिक छात्रों को आकर्षित करने के लिए भारत में अपने सहयोगी स्कूलों की संख्या लगभग एक हजार करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके साथ ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए जर्मनी स्वयं को भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए एक आकर्षक विकल्प के रूप में स्थापित कर रहा है।

वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कारों पर ज्यादा टैरिफ लगाने से जर्मनी नाराज है। जर्मनी अपनी रक्षा के लिए अमेरिकी सैन्य शक्ति पर निर्भर रहा है। वहीं वह यूरोप का नेतृत्व भी करना चाहता है। जर्मनी की पुनः वैश्विक महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षाओं और अमेरिका पर से यूरोप की निर्भरता कम करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक में महारत बेहद जरूरी है। यही कारण है कि जर्मनी की दीर्घकालीन नीतियों और साझेदारी में भारतीय मस्तिष्क उसकी पहली पसंद बन गया है तथा ट्रंप की कड़ी और अदूरदर्शी वीजा नीतियों ने जर्मनी की स्थिति को और अधिक मजबूत कर दिया है। (ब्रह्मदीप अलूने)

खरी-खरी

घर से निकलते ही....

पूरन सरमा

घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, उस्तरा लिए हुए बैठे हैं कुछ पाकेटमार। कितनी ही सावधानी बरती जाए, लेकिन काम करने वाले अपना काम कर ही जाते हैं। यानी चिंता अपने बारे में नहीं करनी है- चिंता का विषय पाकेटमार है। घर से निकलो तो रास्ते में जहरीली चाय पिलाकर लूटने वाले बैठे हैं या फिर नकली नोटों के चक्कर में फंसाने वाले। यही क्यों? आपका अपहरण हो जाएगा अथवा किसी अबला के साथ दुष्कर्म हो जाएगा। गजब ही हो गया साहब, दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। इच्छा होती है कि मारे डर के घर से बाहर ही न निकलें, लेकिन मजबूरी है कि घर से बाहर निकले बिना काम भी नहीं चलता, सो निकलना ही पड़ता है घर से।

समाचार पत्रों को पढ़ो तो इसी तरह की सनसनीखेज घटनाओं से भरे पड़े हैं। उसके बाद भी ठगे जा रहे हैं लोग। कदम-कदम पर ठग विद्या का जाल फैला है। महाठगों की नगरी बनता जा रहा है मेरा शहर। आपकी जेब में जो नोट रखे हैं, पता नहीं नकली तो नहीं हैं। चलाए किसने हैं और क्या आप उन्हें पकड़ पाएंगे। पुलिस को तो जानते ही हैं कि वो निर्दोष की हड्डी पसली एक कर देती है और अपराधी को सुविधा उपलब्ध कराती है घूमने की।

कानून-व्यवस्था की समीक्षा करने की न तो जरूरत है, न यह सामयिक है। सजगता यह रखनी है कि आप स्वयं चौकस हैं या नहीं। लोभ गला कटाता है। सोने के जेवर दोगुने करने वाले या फिर बाजार दर से काफी कम कीमत पर सोना बेचने वाले घूम रहे हैं, जो आपको चूना लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो वे असली सोना लेकर नकली पीतल पकड़ाकर चलते बनते हैं। सरकार का दावा है कि राज्य में कानून और व्यवस्था बहाल है और जो लोग कानून व्यवस्था में खामी निकाल रहे हैं वे राजनीति करते हैं। इसलिए बात सरकार की मानो, ताकि प्राण रक्षा हो सके, अन्यथा पता नहीं किस झूठे मामले में फंसकर आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। सरकार के पास आपको फंसाने के लिए अनेक तरीके हैं, लेकिन आपके पास बचने का उपाय यही है कि केवल अपने बारे में सोचा करो, सरकार के बारे में नहीं।

पोस्ट

एशिया कप में टीम इंडिया ने क्रिकेट का इतिहास लिख दिया। टीम इंडिया ने किसी टूर्नामेंट के एक ही संस्करण में एक ही प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को तीन बार हराया।
सैयद अकबरुद्दीन@AkbaruddinIndia

दुनिया बनेगी-बिगड़ेगी, लोग आएंगे-जाएंगे, लेकिन राजीव शुक्ला बीसीसीआइ के उपाध्यक्ष और अजीत पवार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री बने रहेंगे।
अरविंद चोटिया@arvindchotia

अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक की यह टिप्पणी कूटनीति नहीं, बल्कि अहंकार है कि भारत व ब्राजील जैसे कुछ देश हैं, जिन्हें हमें ठीक करने की जरूरत है। अगर किसी चीज को ठीक करने की जरूरत है, तो वह है ट्रंप प्रशासन का अहंकार भरा रवैया और वह मानसिकता, जो धौंस जमाने को शासन-कौशल समझती है।
ब्रह्म चेलानी@Chellaney

भारतीयों को जोहो साफ्टवेयर एप का प्रयोग कर स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए। जो कहते थे कि भारत अपना एप, साफ्टवेयर क्यों नहीं बनाता, उन्हें इसका प्रयोग करना चाहिए। डा. अवनिंद्र कुमार राय@avanindra43

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या भगदड़ की घटनाएं यही बताती हैं कि पिछली गलतियों से सीख नहीं ली जा रही?

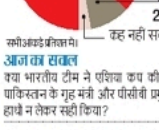

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या भारतीय टीम ने एशिया कप की ट्राफी पाकिस्तान के गृह मंत्री और पीसीबी प्रमुख के हाथों न लेकर सही किया?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

माथे पर सोहे 'तिलक' और मांग 'सिंदूर',
ऐसा भारत पाक को सदा चटाए धूर।
सदा चटाए धूर शूर जब अपने उतरें,
क्रिकेट होय या जंग विरोधी निज नख कुतरें।
भिड़कर हमसे आप उठाओगे बस घाटे,
लौटोगे हर बार हार चिपकाकर माथे!
-ओमप्रकाश तिवारी

जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

बंगाल डायरी

दशक बाद चुनाव प्रभारी की नियुक्ति के मायने

बंगाल में आगामी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य में पार्टी के चुनावी कार्यों की देखरेख के लिए लगभग एक दशक बाद 'प्रभारी' नियुक्त किया है। शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार प्रदेश में सुनील बंसल व मंगल पांडेय जैसे वरिष्ठ नेता पार्टी की प्रदेश इकाई के सांगठनिक और राजनीतिक मामलों के पर्यवेक्षक के रूप में पहले से ही कार्य कर रहे हैं। इस बार एक केंद्रीय मंत्री को केवल चुनाव कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही एक पूर्व मुख्यमंत्री को उनका सहयोगी नियुक्त किया गया है। भाजपा ने 2021 चुनाव में जीत की प्रबल संभावना के बावजूद बंगाल के लिए 'चुनाव प्रभारी' नियुक्त नहीं किया था, परंतु 2026 के विधानसभा चुनाव में 10 वर्ष बाद इस बार चुनाव प्रभारी नियुक्त करने के बाद से यह प्रश्न उठ रहा है कि ऐसा क्यों किया गया है?

भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बीते गुरुवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को 'चुनाव प्रभारी' और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद बिप्लब देब को 'सह-चुनाव प्रभारी' नियुक्त करने की घोषणा की है यानी भूपेंद्र-बिप्लब की जोड़ी चुनाव तक राज्य में उन नेताओं के साथ काम करेगी, जो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। भूपेंद्र यादव ने यह जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया।

वैसे बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को 'चुनाव प्रभारी' नियुक्त करना भाजपा में कोई नई बात नहीं है, परंतु यहां प्रश्न यह है कि क्या इससे राज्य में भाजपा के लिए कोई चमत्कार होगा? इससे पहले 2006 और 2011 में बंगाल विधानसभा चुनाव में अरुण जेटली को 'चुनाव प्रभारी' बनाया गया था। इसके बाद 2016 में निर्मला सीतारमण को यह जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन नतीजा क्या रहा था, यह सर्वविदित है। 2021 में आधिकारिक

भूपेंद्र यादव। फाइल

बिप्लव देव। फाइल

तौर पर किसी को यह जिम्मेदारी नहीं दी गई। उस समय शिव प्रकाश राज्य में 'सांगठनिक पर्यवेक्षक' और कैलाश विजयवर्गीय 'राजनीतिक पर्यवेक्षक' के रूप में कार्य देख रहे थे। शीर्ष नेतृत्व ने भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रबंधन में उनकी मदद के लिए भेजा था। इस बार भूपेंद्र को आधिकारिक तौर पर चुनाव प्रभारी बनाया गया है। प्रदेश भाजपा इस नियुक्ति से खुश है। राज्य भाजपा नेतृत्व का दावा है कि चुनाव की देखरेख की जिम्मेदारी 'उचित' हाथों में सौंपी गई है। यहां के नेताओं का कहना है कि भूपेंद्र यादव पहले भी इस राज्य में चुनावों में काम कर चुके हैं इसलिए वे यहां की चुनावी रणनीति को समझते हैं और उसी के अनुसार मैदान में उतरेंगे। इन दोनों के लिए बंगाल नया नहीं है।

चुनाव प्रबंधन का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली और राज्य के बीच 'समन्वय' के रूप में काम करना भी होता है। यह समन्वय केवल पार्टी के राज्य नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के बीच ही नहीं है। सरकार के साथ भी समन्वय बढ़ाना जरूरी होता है। माना जा रहा है कि यदि भूपेंद्र जैसे पूर्णकालिक मंत्री प्रभारी हों तो यह समन्वय ज्यादा सहज होगा। ऐसे में विभिन्न मामलों में केंद्रीय हस्तक्षेप आसानी से हो सकता है। राज्य भाजपा के कई नेताओं का दावा है कि बंगाल के लिए 'चुनाव प्रभारी' का चुनाव इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर किया गया है। भूपेंद्र-बिप्लब को भाजपा में भरोसेमंद रणनीतिकार माना जाता है। भूपेंद्र यादव ने पिछले बिहार विधानसभा चुनाव समेत राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं बिप्लब कुमार देब इससे पहले हरियाणा के चुनाव में पार्टी के प्रभारी के रूप में काम कर चुके हैं। वह अपने अनुभव और क्षमता से हरियाणा सहित दिल्ली के चुनावों में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं, इसलिए इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने इन दोनों नेताओं पर बंगाल चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है।

दूसरी तरफ बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इस नियुक्ति की आलोचना की है, जैसा कि अपेक्षित था। तृणमूल की ओर से एक्स हैंडल पर बिप्लब देब को 'बिग-फ्लाप देब' लिखा गया। इसके साथ पोस्ट किए गए एक वीडियो में तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा- 'जिस व्यक्ति को भाजपा ने बंगाल में चुनाव की जिम्मेदारी देकर भेजा है, वह बिप्लब देब अपने ही राज्य त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। जो व्यक्ति त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य को संभाल नहीं पाया, जिसे भाजपा ने बीच में ही पद से हटा दिया, उसे बंगाल भेजा है। बंगाल की जनता सब देख रही है। वह सबको एक साथ बिठाकर वापस भेज देगी। प्रदेश भाजपा के नेता तृणमूल के इस कटाक्ष पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

वैसे बंगाल में भूपेंद्र-बिप्लब की जोड़ी के लिए पार्टी स्तर पर कई चुनौतियां होंगी, जिनसे निपटना उनके लिए आसान नहीं होगा। राज्य भाजपा में गुटबाजी, नए-पुराने के बीच द्वंद्व काफी जटिल है। अब देखना है कि विधानसभा चुनाव से पहले इस गुटबाजी से यह जोड़ी कैसे निपटती है और भाजपा को राज्य की सत्ता के शिखर पर पहुंचाने में कामयाब होती है या नहीं।

मंथन

डिजिटल प्रारूप में जनगणना

आगामी जनगणना पूर्णतया डिजिटल होगी। पहले पूरे देश का स्मार्ट मैप बनेगा, जो हर घर को डिजी डाट में बदलेगा। यह पहल एक ऐसी तकनीकी क्रांति होगी जिसके दूरगामी प्रभाव होंगे

संजय श्रीवास्तव
वरिष्ठ पत्रकार

प्रतीकात्मक

आगामी जनगणना के माक ड्रिल का जल्द ही आरंभ होने जा रहा है। बहुआयामी प्रभावों वाली यह पहल देश के लिए क्रांतिकारी साबित होगी। यह महत्वाकांक्षी प्रयास है- डिजिटल लेआउट मैपिंग के जरिए समूचे देश का स्मार्ट नक्शा बनाने का। स्मार्ट मैपिंग तकनीक के माध्यम से पूरा देश एक इंटरएक्टिव डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगा। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। पहले जनगणना या सर्वेक्षण के दौरान हाउस लिस्टिंग के लिए अनुमान के आधार पर हाथ से बने स्केच से लोकेशन तय की जाती थी।

इसका डिजिटलीकरण एक बहुत बड़ा प्रयास है। इस योजना के अंतर्गत देश की आवासीय और गैर-आवासीय सभी इमारतों को जियो-टैग कर स्वचालित रूप से डिजिटल लेआउट तैयार किया जाएगा। जियो-टैग की सहायता से अक्षांश-देशांतर निर्देशांक के आधार पर जीपीएस मानचित्र में उन इमारतों को एक डिजी डाट में बदलना दूरदर्शी परिकल्पना है। प्रत्येक घर या डिजी डाट को 10 अंकों का एक विशेष अल्फा न्यूमरिक डिजी पिन और क्यूआर कोड दिया जाएगा। हर दुकान, प्रतिष्ठान, घर, मंदिर, स्कूल को एक सटीक डिजिटल पता प्राप्त होना वर्तमान में नई बात नहीं, लेकिन समूचे देश में ऐसा प्रचलन बड़ी परिवर्तनकारी घटना होगी। इससे किसी भी घर या इमारत को आनलाइन आसानी से खोजा जा सकेगा।

यदि यह योजना त्रुटिहीन तरीके से पूरे देश में लागू हो जाती है तो यह तकनीक हाउस लिस्टिंग का पुराना तरीका बदल देगी। इससे डाटा संग्रह और विश्लेषण में अभूतपूर्व सटीकता आएगी। जनगणना तकनीकी रूप से उन्नत होगी और उसके आंकड़ों की गुणवत्ता व उपयोगिता भी बहुत बढ़ेगी। इससे जनगणना कर्मियों का समय बचेगा, काम का बोझ घटेगा और लोगों, घरों व परिवारों की संख्या का सटीक अनुमान संभव होगा। इस पूरी प्रक्रिया का व्यापक असर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, निर्माण कार्य, शहरीकरण, कृषि, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा जैसे दर्जनों क्षेत्रों पर सकारात्मक बदलाव के रूप में दिखाई देगा। व्यवस्थाएं अधिक चुस्त-दुरुस्त और पारदर्शी होंगी तथा कार्रवाइयां त्वरित और जनाभिमुख बनेंगी।

चुनौतियां : देश में 33 करोड़ से अधिक घरों पर इसे तकनीकी दक्षता के साथ सफलतापूर्वक लागू करना आसान नहीं है। इसकी चुनौतियों और नुकसानों से निपटने के लिए अतिरिक्त श्रम, व्यय, तकनीकी विशेषज्ञता और अन्य प्रयासों की आवश्यकता होगी। लेकिन यदि सरकार इसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू कर पाती है, तो यह नीति-निर्माण और संसाधनों के विवेकपूर्ण आवंटन की दिशा में एक युगांतरकारी कदम होगा। डिजिटल लेआउट मैपिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत भौगोलिक आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से डिजिटल छवि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे यह बहुविधि उपयोगी बन जाती है। डिजिटल मानचित्रों में विभिन्न स्तर, वर्ग और विषय हो सकते हैं- जैसे सड़कें, इमारतें और प्राकृतिक विशेषताएं। एजेंसियां विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए इन परतों का अपने अनुसार विश्लेषण कर सकती हैं। इससे शहरी नियोजन, भूमि उपयोग, अवसंरचना घनत्व, बसावट और पलायन के पैटर्न समझने में मदद मिलती है।

इस तकनीक के डिजिलाकर, जनधन, स्वास्थ्य मिशन जैसे सरकारी पोर्टलों, योजनाओं से जुड़ने के बाद एकीकृत सेवा वितरण संभव होगा। इससे सभी नागरिकों तक लाभ सीधे पहुंच सकेगा और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। हालांकि स्मार्ट मैप तैयार करने में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अगर शुरुआती डाटा गलत हुआ तो पूरा मैप गलत हो सकता है। भारत में आंकड़ों की स्थिति देखते हुए यह बड़ी आशंका है। नागरिकों की लोकेशन और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता व डाटा सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इसलिए डाटा संग्रह, उपयोग और साझाकरण के लिए पारदर्शी नीतियां चाहिए।

इसके साथ ही साफ्टवेयर, हार्डवेयर और ट्रेनिंग में लागत आती है और बदलते क्षेत्रों के अनुसार मैप को लगातार अपडेट करना पड़ता है। बिजली व इंटरनेट की कमी वाले क्षेत्रों में इसका उपयोग चुनौतीपूर्ण होगा। साथ ही नेट साक्षरता और जन जागरूकता भी जरूरी है, क्योंकि हर कोई डिजिटल मैप को सहजता से नहीं समझ पाता। फिलहाल भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित हर घर का डिजी डाट और स्मार्ट मैपिंग पहल न केवल जनगणना 2027 को डिजिटल रूप देने की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि देश के प्रशासनिक, सामाजिक और तकनीकी ढांचे को नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी है। यह पहल भारत को एक ऐसे डिजिटल युग में प्रवेश दिला सकती है जहां प्रशासन, सेवा वितरण और नागरिक सहभागिता सभी तकनीक के माध्यम से पारदर्शी होंगे। निस्संदेह, यह पहल तकनीकी दृष्टि से क्रांतिकारी है। अब देखना यह है सरकार इस ओर किस प्रतिबद्धता से आगे बढ़ती है। (ईआरसो)

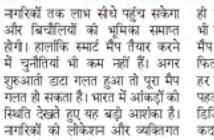

****